

अजीब सा लगा, जब गहलोत व पायलट एक ही मंच पर, गले मिलते, हँसते, गल-बहियां होते नज़र आए

मौका था, कांग्रेस ओबीसी काउंसिल की बैठक का, जो राहुल गांधी ने आहूत की थी

—रेणु मिश्र—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 22 अप्रैल। राजस्थान कांग्रेस के दो ओबीसी नेता, जो आमतौर पर एक-दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाते हैं और एक-दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, हाल ही में हाथ मिलाते, साथ में हँसते और परस्पर समर्थन, प्रेम तथा एकता का संदेश देते हुए देखे गए।

चरित्र नेता अशोक गहलोत ने तस्वीरें खींच रहे फोटोग्राफरों से कहा कि वे इन तस्वीरों को क्लिक करें और सुरक्षित रखें।

दूसरे नेता सचिन पायलट थे। दोनों इंद्रिया भवन में राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई कांग्रेस ओबीसी परिषद की बैठक में उपस्थित थे। दिलचस्प बात यह रही कि राहुल गांधी ने चर्चा की शुरुआत विभिन्न

राहुल गांधी का मैसेज था कि देश के व राज्यों के ओबीसी नेता मिलकर बैठें तथा ओबीसी के मुद्दों पर एक सर्वमान्य राय बनाएं, जिससे यह उभर कर सामने आए कि ओबीसी के कौन से मुद्दे, राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जा सकते हैं।

राहुल ने इसी संदर्भ में आगे कहा कि अब तक उनके पास नेता अपनी व्यक्तिगत परेशानियों लेकर आते थे, यह रूकना चाहिए तथा इन नेताओं को तय करना चाहिए, मिल बैठकर, कि कौन से मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने चाहिए, किन मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

शायद राहुल की इस सोच की अनुपालना में गहलोत और पायलट के प्रेम पूर्वक मिलाप का अद्भुत दृश्य देखने को मिला।

राज्यों और देशभर से आए ओबीसी नेताओं से यह कहकर की कि वे एकजुट हों, साथ आएँ, महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाएं, जिन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की जरूरत है उन्हें तय करें, और फिर सहमति वाले मुद्दों के साथ उनके पास आएँ, ताकि वे उन्हें पार्टी के भीतर और अन्य मंचों पर उठा

सकें। राहुल गांधी ने कहा कि नेता उनके पास व्यक्तिगत रूप से अपने-अपने मुद्दों के साथ आते हैं, लेकिन अब यह बंद होना चाहिए और उन्हें उन अहम मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है।

राहुल गांधी ने उपस्थित ओबीसी

नेताओं से यह भी कहा कि सरकार उनकी जातिगत जनगणना की मांग मान चुकी है, और यह कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए होना ही चाहिए कि ओबीसी, दलित और अन्य वर्गों को सत्ता संरचना में उनका उचित हिस्सा मिल सके, जिसकी वे मांग कर रहे हैं।

आईआरएस अफसर की बेटी की रेप के बाद हत्या

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में बुधवार सुबह एक सीनियर आईआरएस अफसर के घर में उनकी 22 साल की बेटी की रेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, घटना सुबह करीब 6 बजे हुई। युवती घर में अकेली थी।

आईआरएस अफसर और उनकी पत्नी रोज की तरह जिम गए हुए थे। वापस लौटते तो बेटी का शव कमरे में मिला। वह यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। शुरुआती जांच के अनुसार,

पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा को एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। वह उक्त अफसर के घर में नौकर था।

उसके साथ पहले रेप किया गया। फिर मोबाइल चार्जर के तार से गला घोटकर हत्या की गई।

घटना के करीब 14 घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी, 19 साल के राहुल मीणा को गिरफ्तार किया। वह द्वारका इलाके के एक होटल में छिपा हुआ था। वह आईआरएस अफसर के (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

क्या ममता बनर्जी बौखला गई हैं चुनाव की टैशन के कारण

एक के बाद एक इतनी अजीबोगरीब टिप्पणियाँ कर रही हैं, अब जनता ने इन पर ध्यान देना ही बंद कर दिया है

—अंजन राय—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 22 अप्रैल। राज्य विधानसभा चुनावों की पूर्व संघ्या पर, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से एक और कड़ी फटकार मिली।

सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के व्यवहार पर बेहद कड़ी टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने राज्य की मुख्यमंत्री को उस स्थान पर जाने के लिए फटकार लगाई, जहां ईडी कोयला चोरी और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच के सिलसिले में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर रहा था।

बताया गया कि मुख्यमंत्री जबरन वहाँ पहुँचीं और ईडी द्वारा जब्त किए गए दस्तावेज अपने साथ ले गईं। वे राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ ईडी की कार्रवाई के बीच पहुँचीं और एजेंसी

उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा, जलियाँवाला काण्ड के बाद, इस खौफनाक लोमहर्षक घटना के बारे में महात्मा गांधी ने एक भावभीनी कविता लिखी थी, पर यह सर्वविदित है, जिस कविता का ममता जी उल्लेख कर रही हैं, रविन्द्र नाथ टैगोर ने लिखी थी, नोबल पुरस्कार मिलने के बाद।

यहाँ तक कि जब ममता जी ने ईडी के छापे के दौरान, घटना स्थल पर पहुँचकर, ईडी द्वारा जब्त कागजात व फाइलें, अपने पुलिस के जत्थे की मदद से जोर जबरदस्ती से उठा लाईं थी तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब यह मामला पहुँचा ममता जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़े-बड़े वकील पैरवी कर रहे थे।

की आलोचना करते हुए आधिकारिक फाइलें लेकर वहाँ से चली गईं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का व्यवहार भारतीय लोकतंत्र के

इतिहास में अभूतपूर्व है और यह न्याय, निष्पक्षता तथा कार्यपालिका की संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन है। (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

प.बंगाल की 84 एससी/एसटी बहुल सीटें तय करेगी, किसकी सरकार बनेगी

ये सीटें जंगल महल बैल्ट, उत्तरी बंगाल और दक्षिण बंगाल की मातुआ बैल्ट में फैली हैं

—श्रीनंद झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 22 अप्रैल। चूँकि बंगाल में गुरुवार को पहले चरण का मतदान शुरू होता है, इसलिए सभी की नज़रें जंगलमहल क्षेत्र, उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल की 'मातुआ बैल्ट' (जिसमें नदिया और उत्तर 24 परगना जैसे जिले शामिल हैं) में फैली 84 अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) सीटों के मतदान स्थानों पर टिकी हैं।

इन सीटों पर जो भी पार्टी बड़त हासिल करेगी, उसके सरकार बनाने की संभावना अधिक होगी। इन क्षेत्रों में चुनावी मुकाबले को और महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि पिछले कुछ चुनावों में मतदाताओं की बदलती निष्ठाएँ साफ तौर पर दिखाई दी हैं। ये सीटें, जो कभी वाम मोर्चा का अभेद्य गढ़ मानी जाती थीं, अब बंगाल की

वर्ष 2006 तक इस क्षेत्र में वाम मोर्चा का दबदबा था तब इसने यहाँ कि 84 सीटों में से 72 सीटें जीती थीं, पर, 2011 में ममता बनर्जी ने वाम मोर्चा से यह गढ़ छीन लिया। 2016 में भी ममता बनर्जी ने 84 में से 66 सीटें जीती थीं।

लेकिन 2021 के गत विधानसभा चुनावों में भाजपा ने इस क्षेत्र में दबदबा बढ़ाया और 84 में से 39 सीटें जीतीं और तृणमूल (36 सीटें) से बराबरी पर रही। इस बार भाजपा व तृणमूल दोनों पूरा जोर लगा रही हैं कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते।

राजनीति का सर्वाधिक अप्रत्याशित रणक्षेत्र बन गई है। 2006 में वाम मोर्चा ने इन 84 में से 72 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2011 के चुनावों में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की परिवर्तन लहर के बीच उसका पूरी तरह सफाया हो गया। इसके

बाद 2016 के चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने 84 में से 66 सीटें (50 एससी और 16 एसटी) जीतीं। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय पैठ बनाई, तथा उसने 32 (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

चुनाव आयोग ने खड़गे को नोटिस दिया

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कथित तौर पर 'आतंकवादी' कहे जाने के विषय को गंभीरता से लेते हुए उन्हें नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है।

चुनाव आयोग के अधिकारी सूत्रों ने आज इसकी जानकारी दी। तमिलनाडु

खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री को 'आतंकवादी' कहने को आयोग ने गंभीरता से लिया।

में संवाददाता सम्मेलन में खड़गे ने प्रधानमंत्री को कथित तौर पर 'आतंकवादी' कहा था। भारतीय जनता पार्टी ने मामले को गंभीर बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष की प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी की तीखी आलोचना की थी।

इस मुद्दे पर भाजपा का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री किरण रिज्जु के नेतृत्व में आज चुनाव आयोग से मिला था। दूसरी ओर, कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पर सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री को आतंकवादी नहीं कहा, बल्कि उनका अर्थ था कि वे राजनेताओं को डरा रहे हैं।

बंगाल चुनाव में मोटरसाइकिल चलाने पर लगा प्रतिबंध

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए जो "अभूतपूर्व" प्रतिबंध लगाए हैं, उनमें बाइक पर प्रतिबंध को "सबसे ज्यादा अभूतपूर्व" माना जा रहा है।

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 22 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में होने वाले दो चरणों के चुनाव के मद्देनजर मोटरसाइकिलों के उपयोग पर एक अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाया गया है।

चुनाव आयोग ने मतदान से 48 घंटे पहले मोटरसाइकिल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, यहाँ 23 अप्रैल को मतदान है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक वही, मोटर साइकिल चला सकेंगे, जिन्हें अति आवश्यक काम है। आवाजाही प्रतिबन्धित कर दी है, सिवाय "आपातकालीन" और पारिवारिक जरूरतों के। साथ ही, मोटरसाइकिल रैलियों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।

आयोग के बयान में कहा गया है, "मतदान दिवस से दूसरे दिन तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान के उद्देश्य से और अन्य आवश्यक

आयोग ने मतदान के दो दिन पहले से मतदान के अगले दिन तक के लिए बाइक चलाने और पीछे सवारी बिठाने पर रोक लगाई है, केवल आपात स्थिति में ही इसमें छूट दी जा सकती है पर इसके लिए पुलिस थाने में सूचित कर अनुमति लेनी होगी।

आयोग के इस फैसले की भारी आलोचना हो रही है, खासकर गिग वर्कर्स और रैपिडो आदि में बाइक चलाने वालों की तरफ से। उनका कहना है इससे उनके लिए रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाएगा।

(फिलियन राइडिंग) यात्रा की अनुमति नहीं होगी, सिवाय चिकित्सा आपातकाल, पारिवारिक कार्यक्रम आदि के लिए अनुमति दी जाएगी।" चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी प्रकार की छूट के लिए लोग पहले से स्थानीय पुलिस के पास आवेदन कर सकते हैं।

बाद में आयोग ने स्पष्ट किया कि उचित पहचान पत्र सहित दफ्तर जाने वाले लोगों को भी छूट दी जाएगी।

जरूरतों, जैसे चिकित्सा आपातकाल, पारिवारिक कार्यक्रम आदि के लिए अनुमति दी जाएगी।" चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी प्रकार की छूट के लिए लोग पहले से स्थानीय पुलिस के पास आवेदन कर सकते हैं।

बाद में आयोग ने स्पष्ट किया कि उचित पहचान पत्र सहित दफ्तर जाने वाले लोगों को भी छूट दी जाएगी।

आयोग ने कहा कि उसका उद्देश्य "स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और हिंसा-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करना" है। इसी दिशा में, आयोग ने राज्य में शराब बिक्री पर प्रतिबंध की अवधि को पहले ही दोगुना दिया था। सामान्य 48 घंटे का प्रतिबंध बढ़ाकर 96 घंटे कर दिया गया, जो रविवार से लागू हुआ।

19 अप्रैल के एक बयान में चुनाव आयोग ने कहा था, यह देखा गया है कि शराब की बिक्री में असामान्य वृद्धि हुई है। यह निष्कर्ष विभिन्न स्रोतों, जिनमें शराब निगरानी अधिाया भी शामिल हैं, के आधार पर निकाला गया। आयोग के अनुसार, अप्रैल में शराब की बिक्री पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अधिक रही है।

पश्चिम बंगाल में यह हाई-स्टेक विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होंगे, जबकि मतगणना 4 मई को होगी।

लिपुलेख दर्दा से भारत-चीन व्यापार जून में शुरू होगा

पिथौरागढ़, 22 अप्रैल। लिपुलेख दर्रा के माध्यम से भारत-चीन सीमा व्यापार वर्ष 2026 के जून के प्रथम सप्ताह से शुरू होकर सितंबर तक चलेगा। भारत-चीन सीमा व्यापार को वर्ष 2026 में पुनः शुरू करने की तैयारियों को लेकर

करीब 6 साल के बाद यहां से व्यापार शुरू करने की विदेश मंत्रालय ने स्वीकृति दी।

बुधवार को जिलाधिकारी आशीष भट्टगर्ही की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय से लिपुलेख दर्रे के माध्यम से व्यापार शुरू करने की अनापत्ति मिलने के बाद प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

करीब छह वर्षों के अंतराल के बाद फिर से शुरू हो रहे इस सीमा व्यापार को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है और सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ट्रंप ने ईरान के साथ अनिश्चितकाल तक सीज़फायर बढ़ाने का श्रेय पाकिस्तान को दिया

अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ-साफ लिख पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर और पाक प्र.मंत्री शहबाज़ शरीफ के अनुरोध पर वे अनिश्चितकाल के लिए सीज़फायर बढ़ा रहे हैं

—जाल खंबाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 22 अप्रैल। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिका-ईरान युद्धविराम समाप्त होने से कुछ घंटे पहले ही इसे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया, और इसके लिए पाकिस्तान के निवेदन का हवाला दिया। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि वे गंभीर रूप से विभाजित ईरानी शासन को स्थायी शांति समझौते के लिए एकीकृत प्रस्ताव तैयार करने का समय देना चाहते हैं। यह पहली बार है, जब अमेरिका ने तेहरान की अगली कार्रवाई के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की है, और ट्रंप ने अपनी रणनीति में बदलाव का श्रेय पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ हुई बातचीत को दिया है।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच दुध सोशल पर लिखा, इस तथ्य के आधार पर कि ईरान की सरकार गंभीर रूप से विभाजित है, जो अप्रत्याशित नहीं है, और पाकिस्तान के फ़ोल्ड मार्शल आसिम मुनीर तथा प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के अनुरोध पर, हमने ईरान पर अपने हमले तब तक रोकने के लिए कहा है, जब तक उनके नेता और प्रतिनिधि कोई एकीकृत प्रस्ताव लेकर नहीं आते।"

लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में ईरान के तट पर बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी, ट्रंप ने कहा, जबकि अमेरिकी सेना "अन्य सभी मामलों में तैयार और सक्षम" रहेगी। उन्होंने कहा कि युद्धविराम "तब तक बढ़ाया जाएगा, जब तक उनका प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हो जाता और उस पर चर्चा पूरी नहीं हो जाती, किसी भी तरह से।"

ट्रंप ने कहा कि ईरान की सरकार में भारी विभाजन है और जब तक उनकी तरफ से सर्व सम्मत संधि प्रस्ताव नहीं आ जाता, अमेरिकी सेना ईरान पर हमला नहीं करेगी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहेगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि पहले ईरान के नेताओं ने शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान का आभार जताया था और अमेरिका भी पाकिस्तान को श्रेय दे रहा है, इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान की कूटनीतिक ताकत बढ़ेगी।

उपवाद और कमज़ोर अर्थव्यवस्था के कारण दुनिया भर में समस्याग्रस्त राष्ट्र के रूप में देखा जाने वाला देश पाकिस्तान अब अचानक सुर्खियों में आ गया है। पर, मध्यस्थ की यह भूमिका कांटों का ताज है। अगर शांति वार्ता विफल रही तो इसका प्रभाव पाकिस्तान को भी झेलना होगा।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बाद में युद्धविराम बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार करने और उसके "कूटनीतिक प्रयासों" पर "विश्वास और भरोसा" दिखाने के लिए ट्रंप का धन्यवाद किया।

उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरी ओर से और फ़ोल्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ओर से, मैं राष्ट्रपति ट्रंप का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए

युद्धविराम बढ़ाया, ताकि चल रहे कूटनीतिक प्रयास आगे बढ़ सकें। पाकिस्तान इस विश्वास और भरोसे के साथ अपने प्रयास जारी रखेगा बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सके।"

उन्होंने आगे कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष युद्धविराम का पालन करेंगे और इस्लामाबाद में निर्धारित दूसरे दौर की वार्ता के दौरान एक व्यापक "शांति समझौते" पर पहुंच सकेंगे, जिससे संघर्ष का स्थायी अंत हो सके।

यदि इस्लामाबाद वास्तव में ट्रंप को ईरान पर आगे के हमलों को रोकने के लिए प्रभावित कर पाया है, तो इससे उसकी कूटनीतिक स्थिति को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक स्तर पर उसकी साख मजबूत होगी।

इससे पहले, ईरानी नेताओं ने भी कई मौकों पर पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया था। ईरान और अमेरिका के बीच मतभेदों को कम करने के लिए पाकिस्तान के तेज प्रयासों के पीछे (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

संजय झा फिर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने

पटना, 22 अप्रैल। बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किए

गए हैं। इस फेरबदल को आगामी चुनावों के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जदयू की नई टीम में संजय झा को एक बार फिर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, जहानाबाद के पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। गोपालगंज से सांसद आलोक कुमार सुपुन को पार्टी का राष्ट्रीय (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सांसद आलोक कुमार सुपुन को गोपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

विचार बिन्दु

अपनी करनी कभी निष्फल नहीं जाती। -कबीर

राजस्थान के राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय सेवा अपील अधिकरण की आवश्यकता

राजस्थान में न्याय व्यवस्था एक विचित्र विरोधाभास प्रस्तुत करती है। एक ओर राज्य सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए 1 जुलाई 1976 को स्थापित राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षक और कर्मचारी आज भी अपने बुनियादी अधिकारों के लिए वर्षों तक उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाने को विवश हैं।

राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत गठित इस अधिकरण ने सेवा विवादों-जैसे वेतन निर्धारण, पदोन्नति, वरिष्ठता और पेंशन-के त्वरित निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह न केवल उच्च न्यायालय के बोझ को कम करता है, बल्कि कर्मचारियों को अपेक्षाकृत सस्ता और शीघ्र न्याय भी उपलब्ध कराता है। वर्ष 2022 में लगभग 7000 प्रकरण लंबित होने के बावजूद, मई 2023 में जोधपुर में स्थायी पीठ की स्थापना यह दर्शाती है कि सरकार आवश्यकता के अनुसार संस्थागत समाधान विकसित करने में सक्षम है।

इसके विपरीत, विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए ऐसी कोई समर्पित व्यवस्था नहीं है। यह स्थिति मात्र प्रशासनिक कमी नहीं, बल्कि एक गहरी नीतिगत असमानता का संकेत है। प्रश्न उठता है-क्या विश्वविद्यालय कर्मी राज्य व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? क्या उनके सेवा विवाद कम महत्वपूर्ण हैं?

राजस्थान में न्याय व्यवस्था का एक विचित्र और चिंताजनक विरोधाभास सामने आता है। एक ओर राज्य सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों के समाधान के लिए 1976 से एक सशक्त और समर्पित मंच राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत हजारों शिक्षक और कर्मचारी आज भी अपने बुनियादी सेवा अधिकारों के लिए वर्षों तक उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाने को मजबूर हैं।

यह स्थिति केवल प्रशासनिक कमी नहीं, बल्कि एक गंभीर नीतिगत असमानता का उदाहरण है। प्रश्न उठता है कि क्या विश्वविद्यालय कर्मी राज्य व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? क्या उनके सेवा विवाद कम महत्वपूर्ण हैं? या फिर उनकी पीड़ा शासन-प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल ही नहीं है?

राजस्थान के 25 से अधिक विश्वविद्यालयों में कार्यरत हजारों कर्मचारी-चाहे वे शिक्षक हों या अशैक्षणिक-पदोन्नति, वेतन निर्धारण, वरिष्ठता और पेंशन जैसे मामलों में न्याय के लिए वर्षों तक भटकते रहते हैं। अनेक मामलों में तो यह विडंबना देखने को मिलती है कि कर्मचारी सेवा निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उनका मामला अदालत में लंबित ही रहता है। पेंशन जैसे जीवन-निर्वाह के मूल अधिकार के लिए भी उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है।

स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के पेंशनरों का मामला एक दशक से अधिक समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। इसी प्रकार महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के पेंशनरों के कई प्रकरण पाँच वर्षों से लंबित हैं। यह केवल कुछ उदाहरण हैं; वास्तविकता यह है कि ऐसे सैकड़ों मामलों राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्षों से अटक पड़े हैं।

उच्च न्यायालय की अपनी सीमाएँ हैं। वह पहले से ही आपराधिक, दीवानी और संवैधानिक मामलों के अत्यधिक दबाव में कार्य कर रहा है। सेवा संबंधी मामलों अत्यंत तकनीकी होते हैं, जिनमें सेवा नियमों, विश्वविद्यालय अधिनियमों और यूजीसी के विनियमों की गहन समझ आवश्यक होती है। ऐसे में यह अपेक्षा करना कि उच्च न्यायालय इन मामलों का त्वरित और विशेषज्ञतापूर्ण निस्तारण करेगा, व्यावहारिक नहीं है।

यही कारण है कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक पृथक अधिकरण की व्यवस्था की थी। इस अधिकरण ने पिछले लगभग पाँच दशकों में यह सिद्ध कर दिया है कि विशेषीकृत मंच न्याय को तेज, सस्ता और प्रभावी बना सकता है। वर्ष 2022 में भी इसके समक्ष हजारों मामलों लंबित थे, जिसके समाधान हेतु 2023 में जोधपुर में स्थायी पीठ की स्थापना की गई। इससे स्पष्ट है कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर संस्थागत समाधान विकसित कर सकती है।

फिर प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालय कर्मियों को इस सुविधा से वंचित क्यों रखा गया है? यह केवल न्याय में देरी का मुद्दा नहीं है, बल्कि न्याय से वंचित करने की स्थिति है। न्याय में देरी, अन्याय के समान है-यह उचित विश्वविद्यालय कर्मियों की स्थिति पर पूरी तरह लागू होती है। जब किसी सहायक प्रोफेसर का पदोन्नति मामला आठ-दस वर्षों तक लंबित रहता है, तो उसका पूरा कैरियर प्रभावित होता है। जब किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन वर्षों तक अटक रही है, तो यह उसके सम्मानजनक जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।

इस समस्या का समाधान स्पष्ट और व्यावहारिक है-राजस्थान में विश्वविद्यालय सेवा अपील अधिकरण की स्थापना। यह अधिकरण विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करेगा, जहाँ उनके सेवा संबंधी विवादों का त्वरित और विशेषज्ञतापूर्ण निस्तारण हो सकेगा।

ऐसे अधिकरण में शिक्षा प्रशासन और सेवा नियमों के जानकार विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए, जो विश्वविद्यालयों की जटिल संरचना और नियमों को भली-भाँति समझते हों। इसके साथ ही, मामलों के निस्तारण के लिए एक निश्चित समय-सीमा-जैसे 180 दिन-निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि वर्षों तक लंबित रहने की समस्या समाप्त हो सके।

इस अधिकरण की क्षेत्रीय पीठें जयपुर के साथ-साथ जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर जैसे प्रमुख स्थानों पर स्थापित की जा सकती हैं। इससे कर्मचारियों को अपने ही क्षेत्र में सुलभ और किफायती न्याय मिल सकेगा। वर्तमान में उच्च न्यायालय तक पहुँचाना न केवल महंगा है, बल्कि समय और संसाधनों की दृष्टि से भी कठिन है।

इस पहल का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि उच्च न्यायालय पर बढ़ते बोझ में कमी आएगी। सेवा संबंधी सैकड़ों मामलों अधिकरण में स्थानांतरित होने से उच्च न्यायालय जटिल संवैधानिक और जनहित के मामलों पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकेगा।

आज जब सरकार ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ़ लिविंग की बात करती है, तब ईज ऑफ़ जिस्टिस को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यह केवल आम नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि उन शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए भी आवश्यक है, जो समाज के बौद्धिक और नैतिक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो वर्ग समाज को दिशा देने का कार्य करता है, वहीं अपने अधिकारों के लिए वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा करता है। यह स्थिति न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

राज्य सरकार को इस दिशा में शीघ्र और ठोस कदम उठाने चाहिए। विश्वविद्यालय सेवा अपील अधिकरण की स्थापना की घोषणा एक ऐतिहासिक और स्वागतयोग्य पहल होगी। इससे न केवल हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि शासन की न्यायिक संवेदनशीलता भी प्रदर्शित होगी।

अब समय आ गया है कि विश्वविद्यालय कर्मियों को भी वही अधिकार और सुविधाएँ प्रदान की जाएँ, जो राज्य के अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। न्याय में समानता लोकतंत्र की मूल भावना है, और इस सिद्धांत से किसी भी वर्ग को वंचित नहीं किया जा सकता।

यदि सरकार वास्तव में न्यायपूर्ण और समावेशी व्यवस्था स्थापित करना चाहती है, तो उसे इस लंबे समय से लंबित मांग पर तत्काल निर्णय लेना होगा। अन्यथा, विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए तारीख पर तारीख को यह अंतहीन प्रतीक्षा यूँ ही जारी रहेगी-और न्याय केवल एक दूर का सपना बनकर रह जाएगा।

-अतिथि सम्पादक,
डा. पी. सी. कंठालिया,
पूर्व प्रोफेसर एवं मुख्या प्रुदा वैज्ञानिक
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय, उदयपुर

विकसित राजस्थान @ 2047: एक दूरदर्शी, बहुआयामी और रूपांतरणकारी विकास दृष्टि



सी. पी. मण्डावरिया

राजस्थान अपनी गौरवशाली ऐतिहासिक परंपराओं, अद्वितीय स्थापत्य वैभव और समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक बहुलता के कारण वैश्विक पटल पर एक विशिष्ट प्रदेश के रूप में प्रतिष्ठित है। वर्तमान समय राज्य के लिए एक निर्णायक संक्रमण-काल है, जहाँ विकास की केवल मात्रात्मक उपलब्धियों तक सीमित न रहकर गुणात्मक परिष्कार और दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्थायित्व सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित विकसित राजस्थान @2047 विजन दस्तावेज इसी व्यापक संकल्पना को एक ठोस रणनीतिक दिशा प्रदान करता है। इसका महात्वाकांक्षी उद्देश्य राजस्थान को वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की विशाल अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना तथा उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से नागरिकों की औसत जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष या उससे अधिक तक पहुँचाना है। राजिगंज राजस्थान की अवधारणा के माध्यम से राज्य एक सुदृढ़ निवेश-अनुकूल पारिस्थितिकी और पारदर्शी शासन प्रणाली स्थापित कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। यह विजन केवल आर्थिक लक्ष्यों का समूह नहीं है, बल्कि प्रत्येक राजस्थानी के जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन लाने का एक पवित्र संकल्प है।

आर्थिक पुनर्संरचना और 4.3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य :- राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पारंपरिक संसाधन-आधारित मॉडल की सीमाओं से बाहर निकालकर ज्ञान-संचालित और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी समर्थित औद्योगिक ढाँचे में परिवर्तित करना इस विजन का मुख्य मूलाधार है। राज्य को उत्तर भारत के अठगणी मैनुफैक्चरिंग तटवर्ती राज्यों के रूप में स्थापित करने के लिए औद्योगिक गलियारों, निर्यात-उन्मुख इकाइयों और सुदृढ़ डिजिटल व्यापार

जल संचयन की प्राचीन प्रणालियों को आधुनिक भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और सैटेलाइट इमेजरी से जोड़कर जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों में ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज नीति का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करना तथा जल पुनर्चक्रण को प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य बनाना आने वाली पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक सुरक्षा की मजबूत आधारशिला रखेगा। जल स्वावलंबन के माध्यम से ही राज्य अपनी कृषि और उद्योग दोनों को भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षित कर सकता है।

ऊर्जा-परिवर्तन :- हरित भविष्य की आधारशिला :-राजस्थान अपनी अपार सौर और पवन ऊर्जा क्षमता के कारण भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में एक अग्रणी साक्षी के रूप में उभरा है। हरित हाइड्रोजन, उन्नत ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और स्मार्ट-ग्रिड आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर राज्य को नेट-ज़ीरो लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आठसर किया जा रहा है। जैसलमेर और बीकानेर जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों को अक्षय ऊर्जा उत्पादन के वैश्विक केंद्रों के रूप में विकसित करना ऊर्जा आत्मनिर्भरता और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन दोनों ही दृष्टिकोणों से रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरित ऊर्जा आधारित यह औद्योगिक विस्तार न केवल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करेगा, बल्कि राज्य में स्वच्छ निवेश के नए द्वार खोलकर दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और पर्यावरणीय शुद्धता भी सुनिश्चित करेगा।

मानव पूंजी और सामाजिक सशक्तिकरण :-किसी भी विकसित और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का वास्तविक मूल आधार उसकी मानव पूंजी होती है। राज्य की शिक्षा प्रणाली को आलोचनात्मक चिंतन, अनुसंधान उन्मुख दृष्टिकोण और वैश्विक तकनीकी दक्षता पर आधारित बनाना आज की महती आवश्यकता है। डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेली मेडिसिन सेवासों और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के विस्तार से औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि का लक्ष्य

जल-सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन :-रेगिस्तानी और विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राजस्थान के लिए जल प्रबंधन केवल एक नीतिगत विषय नहीं, बल्कि एक अतिव्यवहार आवश्यकता है। रामजल सेतु परियोजना और सुष्म सिंचाई प्रणालियों का व्यापक क्षेत्रीय जल-असंतुलन को दूर करने की दिशा में एक अत्यंत निर्णायक कदम सिद्ध हो रहा है। पारंपरिक वर्षा

जल संचयन की प्राचीन प्रणालियों को आधुनिक भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और सैटेलाइट इमेजरी से जोड़कर जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों में ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज नीति का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करना तथा जल पुनर्चक्रण को प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य बनाना आने वाली पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक सुरक्षा की मजबूत आधारशिला रखेगा। जल स्वावलंबन के माध्यम से ही राज्य अपनी कृषि और उद्योग दोनों को भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षित कर सकता है।

ऊर्जा-परिवर्तन :- हरित भविष्य की आधारशिला :-राजस्थान अपनी अपार सौर और पवन ऊर्जा क्षमता के कारण भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में एक अग्रणी साक्षी के रूप में उभरा है। हरित हाइड्रोजन, उन्नत ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और स्मार्ट-ग्रिड आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर राज्य को नेट-ज़ीरो लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आठसर किया जा रहा है। जैसलमेर और बीकानेर जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों को अक्षय ऊर्जा उत्पादन के वैश्विक केंद्रों के रूप में विकसित करना ऊर्जा आत्मनिर्भरता और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन दोनों ही दृष्टिकोणों से रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरित ऊर्जा आधारित यह औद्योगिक विस्तार न केवल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करेगा, बल्कि राज्य में स्वच्छ निवेश के नए द्वार खोलकर दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और पर्यावरणीय शुद्धता भी सुनिश्चित करेगा।

मानव पूंजी और सामाजिक सशक्तिकरण :-किसी भी विकसित और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का वास्तविक मूल आधार उसकी मानव पूंजी होती है। राज्य की शिक्षा प्रणाली को आलोचनात्मक चिंतन, अनुसंधान उन्मुख दृष्टिकोण और वैश्विक तकनीकी दक्षता पर आधारित बनाना आज की महती आवश्यकता है। डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेली मेडिसिन सेवासों और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के विस्तार से औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि का लक्ष्य

जल-सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन :-रेगिस्तानी और विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राजस्थान के लिए जल प्रबंधन केवल एक नीतिगत विषय नहीं, बल्कि एक अतिव्यवहार आवश्यकता है। रामजल सेतु परियोजना और सुष्म सिंचाई प्रणालियों का व्यापक क्षेत्रीय जल-असंतुलन को दूर करने की दिशा में एक अत्यंत निर्णायक कदम सिद्ध हो रहा है। पारंपरिक वर्षा

जल संचयन की प्राचीन प्रणालियों को आधुनिक भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और सैटेलाइट इमेजरी से जोड़कर जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों में ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज नीति का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करना तथा जल पुनर्चक्रण को प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य बनाना आने वाली पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक सुरक्षा की मजबूत आधारशिला रखेगा। जल स्वावलंबन के माध्यम से ही राज्य अपनी कृषि और उद्योग दोनों को भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षित कर सकता है।

ऊर्जा-परिवर्तन :- हरित भविष्य की आधारशिला :-राजस्थान अपनी अपार सौर और पवन ऊर्जा क्षमता के कारण भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में एक अग्रणी साक्षी के रूप में उभरा है। हरित हाइड्रोजन, उन्नत ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और स्मार्ट-ग्रिड आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर राज्य को नेट-ज़ीरो लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आठसर किया जा रहा है। जैसलमेर और बीकानेर जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों को अक्षय ऊर्जा उत्पादन के वैश्विक केंद्रों के रूप में विकसित करना ऊर्जा आत्मनिर्भरता और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन दोनों ही दृष्टिकोणों से रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरित ऊर्जा आधारित यह औद्योगिक विस्तार न केवल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करेगा, बल्कि राज्य में स्वच्छ निवेश के नए द्वार खोलकर दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और पर्यावरणीय शुद्धता भी सुनिश्चित करेगा।

मानव पूंजी और सामाजिक सशक्तिकरण :-किसी भी विकसित और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का वास्तविक मूल आधार उसकी मानव पूंजी होती है। राज्य की शिक्षा प्रणाली को आलोचनात्मक चिंतन, अनुसंधान उन्मुख दृष्टिकोण और वैश्विक तकनीकी दक्षता पर आधारित बनाना आज की महती आवश्यकता है। डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेली मेडिसिन सेवासों और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के विस्तार से औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि का लक्ष्य

जल-सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन :-रेगिस्तानी और विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राजस्थान के लिए जल प्रबंधन केवल एक नीतिगत विषय नहीं, बल्कि एक अतिव्यवहार आवश्यकता है। रामजल सेतु परियोजना और सुष्म सिंचाई प्रणालियों का व्यापक क्षेत्रीय जल-असंतुलन को दूर करने की दिशा में एक अत्यंत निर्णायक कदम सिद्ध हो रहा है। पारंपरिक वर्षा

जल संचयन की प्राचीन प्रणालियों को आधुनिक भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और सैटेलाइट इमेजरी से जोड़कर जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों में ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज नीति का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करना तथा जल पुनर्चक्रण को प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य बनाना आने वाली पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक सुरक्षा की मजबूत आधारशिला रखेगा। जल स्वावलंबन के माध्यम से ही राज्य अपनी कृषि और उद्योग दोनों को भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षित कर सकता है।

ऊर्जा-परिवर्तन :- हरित भविष्य की आधारशिला :-राजस्थान अपनी अपार सौर और पवन ऊर्जा क्षमता के कारण भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में एक अग्रणी साक्षी के रूप में उभरा है। हरित हाइड्रोजन, उन्नत ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और स्मार्ट-ग्रिड आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर राज्य को नेट-ज़ीरो लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आठसर किया जा रहा है। जैसलमेर और बीकानेर जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों को अक्षय ऊर्जा उत्पादन के वैश्विक केंद्रों के रूप में विकसित करना ऊर्जा आत्मनिर्भरता और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन दोनों ही दृष्टिकोणों से रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरित ऊर्जा आधारित यह औद्योगिक विस्तार न केवल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करेगा, बल्कि राज्य में स्वच्छ निवेश के नए द्वार खोलकर दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और पर्यावरणीय शुद्धता भी सुनिश्चित करेगा।

मानव पूंजी और सामाजिक सशक्तिकरण :-किसी भी विकसित और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का वास्तविक मूल आधार उसकी मानव पूंजी होती है। राज्य की शिक्षा प्रणाली को आलोचनात्मक चिंतन, अनुसंधान उन्मुख दृष्टिकोण और वैश्विक तकनीकी दक्षता पर आधारित बनाना आज की महती आवश्यकता है। डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेली मेडिसिन सेवासों और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के विस्तार से औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि का लक्ष्य

जल-सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन :-रेगिस्तानी और विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राजस्थान के लिए जल प्रबंधन केवल एक नीतिगत विषय नहीं, बल्कि एक अतिव्यवहार आवश्यकता है। रामजल सेतु परियोजना और सुष्म सिंचाई प्रणालियों का व्यापक क्षेत्रीय जल-असंतुलन को दूर करने की दिशा में एक अत्यंत निर्णायक कदम सिद्ध हो रहा है। पारंपरिक वर्षा

जल संचयन की प्राचीन प्रणालियों को आधुनिक भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और सैटेलाइट इमेजरी से जोड़कर जल संसाधनों के वैज्ञानिक एवं प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों में ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज नीति का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करना तथा जल पुनर्चक्रण को प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य बनाना आने वाली पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक सुरक्षा की मजबूत आधारशिला रखेगा। जल स्वावलंबन के माध्यम से ही राज्य अपनी कृषि और उद्योग दोनों को भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षित कर सकता है।

डिजिटल व एआई युग में लेखकों के कॉपीराइट संरक्षण की चुनौती

विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस विशेष.....



विकास आसावत

किताबें एक ऐसी प्रकाश पुंज की तरह हैं जो हर नए पृष्ठ के साथ हमें नए व्यक्तियों, संस्कृतियों और विचारों से अवगत कराती हैं। हर वर्ष 23 अप्रैल को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाता है। यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया यह वार्षिक उत्सव, हमारी दुनिया को आकार देने में पुस्तकों द्वारा निभाई जाने वाली अमूल्य भूमिका और रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा के महत्व को याद

दिलाता है। किताबें महज पत्रे नहीं हैं-वे ज्ञान, कल्पना और नवाचार के द्वार हैं। नियमित पाठन से संज्ञानात्मक क्षमताएं, शब्दावली में अतिरिक्त विस्तार, संवेदना, समीक्षात्मक चिंतन कौशल, समस्या-समाधान क्षमता और अधिक रचनात्मकता का विकास होता है। हमें यह याद रखना होगा कि आज विश्व पुस्तक दिवस है के साथ साथ कॉपीराइट दिवस भी है। इस अधिकार से लेखकों को उनकी रचना के प्रकाशन, अनुवाद, रूपांतरण, या अन्य कोई आर्थिक गतिविधि समबन्धित निर्णय लेने की शक्ति मिलती है।

ई-पुस्तकें और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने साहित्य तक पहुँच को उल्लेखनीय रूप से लोकतांत्रिक बना दिया है और अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर महानगर तक पाठक अपना प्रसन्नता साहित्य, दुर्लभ पुस्तकें, मूल पांडुलिपियाँ, ऐतिहासिक अभिलेखागार, और अन्य संग्रह को अपनी स्क्रीन पर भी पढ़ सकता है। डिजिटल एडिशनस भौतिक स्टोरेज, परिवहन और उपलब्धता की बाधाओं को कम करने के साथ ही फॉट आकार और खोज क्षमताओं जैसे फीचर्स प्रदान

करते हैं व पर्यावरणीय प्रभाव जैसे कागज उत्पादन और वितरण का एक भरोसेमंद विकल्प प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल रचनाओं को लेखक की अनुमति के बिना आसानी से वृद्ध संख्या में कॉपी और वितरित किया जा सकता है। वहीं एआई द्वारा निर्मित रचना के लेखक और उसके कॉपीराइट अधिकार को निर्धारित करना कठिन है। एआई द्वारा निर्मित सामग्री पर कॉपीराइट नहीं हो सकता जब तक कि आपने स्पष्ट रूप से रचनात्मक योगदान न दिया हो।

वहीं, एआई के उपयोग से नकली सामग्री बनाना या संरक्षित रचनाओं की धार्यरी जैसे कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है।

समाधान की बात करे तो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसिंग, सदस्यता मॉडल, स्वयंक्रियण ऑडि अड्डे विकल्प हैं जिसेके लिए पाठक भी सामग्री तक सुविधाजनक और कानूनी पहुँच के लिए भुगतान करने को तैयार है। वहीं युवाओं और अन्य पाठकों में भी कॉपीराइट डेवटेंट को सम्मान करने की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए जागरूकता अभियान को जरूरत है ताकि उल्लंघन को कम किया जा सके।

पुस्तक समेत किसी भी कार्य का

कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है लेकिन रजिस्ट्रेशन से आपको अपने कार्य के निर्धारण व निर्धारण तिथि से संबंधित एक वैधानिक प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाता है। वर्तमान में कॉपीराइट जुरिस्प्रूडेंस "मांड्रिकम ऑफ़ क्रिएटिविटी" पे आधारित है व कार्य के कॉपीराइट पात्रता के लिए न्यूनतम रचनात्मकता का होने आवश्यक है, अतः किसी भी कृति की अभिव्यक्ति में एक विशिष्ट शैली का आभास हो व कॉपीराइट अधिकार को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

शैक्षणिक गतिविधियों के सन्दर्भ में कार्य का रजिस्ट्रेशन या फोटोकॉपी व नॉन कर्माश्रित एक्टिविटीज जैसे कि सामाजिक जागरूकता के लिए ड्रामा या प्ले आदि जिसमें दर्शक या श्रोता से कोई अड्डा रहेगा। चलेते कार्य में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुरगमता से बनने लगेंगे।

किताब लिखना कल्पना, रचनात्मकता, कौशल के साथ साथ बहुत परिश्रम व धैर्य का काज है। आज हम न केवल शिक्षा और प्रेरणा देने की किताबों की शक्ति का उत्सव मना रहे हैं, बल्कि उनके पीछे की रचनात्मक प्रतिभाओं की रक्षा करने में कॉपीराइट के महत्व को भी चिन्हित कर रहे हैं। यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया यह वार्षिक उत्सव, हमारी दुनिया को आकार देने में पुस्तकों द्वारा निभाई जाने वाली अमूल्य भूमिका और रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा के महत्व को याद दिलाता है।

-विकास आसावत,
पेटेंट अटॉर्नी एवं एडवोकेट

सामूहिक आर्थिक सहभागिता को निरंतर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे विकास को मुख्यधारा का लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके। विकसित राजस्थान @ 2047 केवल आर्थिक विस्तार का कोई शुष्क दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक समेकित सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण का विस्तृत रोडमैप है। इसका अंतिम लक्ष्य केवल ऊंचे सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों तक सीमित रहना नहीं है, अपितु एक अत्यंत न्यायपूर्ण, समतामूलक और संवेदनशील समाज के पुनर्स्थापना कागज में एक सक्रिय और जिम्मेदार भागीदार की भूमिका निभाएगा।

उपसंहार: साझा भविष्य की संकल्पना :-जब राज्य की दूरदर्शी नीतियाँ, प्रशासनिक पारदर्शिता और सक्रिय नागरिक सहभागिता एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य में समाहित होंगी, तब 2047 का राजस्थान वैश्विक स्तर से प्रगतिशील और सामाजिक रूप से संतुलित और सामाजिक रूप से समावेशी प्रदेश के रूप में अपनी अमिट पहचान स्थापित करेगा। यह स्वर्णमयी दृष्टि तभी पूर्णतः साकार होगी जब प्रदेश का प्रत्येक नागरिक स्वयं को केवल एक लाभार्थी की मानसिकता से ऊपर उठाकर विकास यात्रा में एक सक्रिय और जिम्मेदार भागीदार की भूमिका निभाएगा।

सामूहिक उत्तरदायित्व, अद्वैत नैतिक प्रतिबद्धता और नवोन्मेषी सोच के समन्वय से ही राजस्थान अपने गौरवशाली अतीत और आधुनिक युग की आकांक्षाओं के मध्य एक संतुलित, स्थायी और संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणादायक भविष्य का निर्माण कर सकेगा। वर्तमान में राजस्थान देश का एक प्रमुख ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है और राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपये के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर चुकी है। वर्ष 2028-29 तक 350 अरब डॉलर और अंततः 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक अत्यंत इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम का निर्माण करना अनिवार्य है। यहाँ पर मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नैस का सिद्धांत केवल एक नारा न रहकर एक जीवंत यथार्थ में परिवर्तित हो जाता है। राजिगंज राजस्थान 2024 के सफल आयोजन के अंतर्गत लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एमआय पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से 8.15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएँ धरातल पर क्रियान्वित होंगी की प्रक्रिया में हैं।

सी. पी. मण्डावरिया,
संयुक्त शासन सचिव,
मानिटरिंग, आयोजना विभाग,
राजस्थान सरकार।

सामूहिक उत्तरदायित्व, अद्वैत नैतिक प्रतिबद्धता और नवोन्मेषी सोच के समन्वय से ही राजस्थान अपने गौरवशाली अतीत और आधुनिक युग की आकांक्षाओं के मध्य एक संतुलित, स्थायी और संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणादायक भविष्य का निर्माण कर सकेगा। वर्तमान में राजस्थान देश का एक प्रमुख ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है और राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपये के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर चुकी है। वर्ष 2028-29 तक 350 अरब डॉलर और अंततः 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक अत्यंत इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम का निर्माण करना अनिवार्य है। यहाँ पर मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नैस का सिद्धांत केवल एक नारा न रहकर एक जीवंत यथार्थ में परिवर्तित हो जाता है। राजिगंज राजस्थान 2024 के सफल आयोजन के अंतर्गत लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के एमआय पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से 8.15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएँ धरातल पर क्रियान्वित होंगी की प्रक्रिया में हैं।

सी. पी. मण्डावरिया,
संयुक्त शासन सचिव,
मानिटरिंग, आयोजना विभाग,
राजस्थान सरकार।

सामूहिक उत्तरदायित्व, अद्वैत नैतिक प्रतिबद्धता और नवोन्मेषी सोच के समन्वय से ही राजस्थान अपने गौरवशाली अतीत और आधुनिक युग की आकांक्षाओं के मध्य एक संतुलित, स्थायी और संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणादायक भविष्य का निर्माण कर सकेगा। वर्तमान में राजस्थान देश का एक प्रमुख ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है और राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपये के महत्वपूर्ण स्तर को पार कर चुकी है। वर्ष 2028-29 तक 350 अरब डॉलर और अंततः 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक अत्यंत इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम का निर्माण करना अनिवार्य है। यहाँ पर मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिम

अंतरराज्यीय ट्रैक्टर तस्करी सिंडिकेट का सरगना सीआईडी के हथ्थे चढ़ा

आरोपी पिछले 12 साल से फरार है, उस पर 50 हजार रु. का इनाम घोषित है

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। सीआईडी (सीबी) पुलिस मुख्यालय की स्पेशल टीम ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 वर्षों से फरार चल रहे 50 हजार रुपए के इनाम अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी अंतरराज्यीय ट्रैक्टर वाहन तस्करी सिंडिकेट का सरगना बताया जा रहा है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर गिराह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है।
पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश और अतिरिक्त महानिदेशक (अपराध) विपिन कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। आरोपी आबिद मेवाती पुत्र खुशीला, निवासी जंगली का नगला,



आरोपी आबिद मेवाती

थाना बरसाना, जिला मथुरा को वहीं से दस्तयाब किया गया।
महानिरीक्षक पुलिस परम ज्योति के सुपरविजन में उपनिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम को सूचना मिली कि आरोपी मथुरा में एक

■ बताया जा रहा है कि आरोपी वर्ष 2012 से इस अवैध कारोबार में सक्रिय था और अब तक 1500 से 2000 से अधिक ट्रैक्टरों की अवैध बिक्री कर चुका है। प्रत्येक वाहन पर करीब 2 लाख रुपए तक का मुनाफा कमाया जाता था।

शुद्धी समारोह में शामिल होने आने वाला है। इस पर टीम ने स्थानीय पुलिस और बूंदी पुलिस को मदद से कुसुम वाटिका में घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया।
अतिरिक्त महानिदेशक (अपराध) विपिन कुमार पाण्डेय ने बताया कि कार्रवाई के दौरान उग्र भीड़ ने आरोपी को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन टीम ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए आरोपी को सुरक्षित हिरासत में लेकर पुलिस थाना हाईवे, मथुरा पहुंचाया, जहां से

उसे बूंदी पुलिस को सुपुर्द किया गया।
जॉर्ज में सामने आया कि आरोपी अपने गिराह के साथ मिलकर अलग-अलग राज्यों में ट्रैक्टर लोन पर खरीदता था, फिर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें टों में लोड कर उत्तर प्रदेश के छाता क्षेत्र में भेज देता था। वहां इन वाहनों की अवैध खरीद-फरोख्त कर भारी मुनाफा कमाया जाता था। बताया जा रहा है कि आरोपी वर्ष 2012 से इस अवैध कारोबार में सक्रिय था और अब तक 1500 से 2000 से अधिक ट्रैक्टरों

भव्या योजना से औद्योगिक विकास को मिलेगी गति

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान में अत्याधुनिक औद्योगिक हब विकसित करने एवं भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उद्यमियों को बेहतर अवसरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की भव्या योजना के अंतर्गत 5 औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा है।
केंद्र सरकार द्वारा भव्या योजना (बिल्डिंग हाई इम्पेक्ट वैल्यू यार्ड्स फॉर एक्सलरेटेड डवलपमेंट) देश में औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू की गई है जिसे दो चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। प्रत्येक चरण में 50 औद्योगिक क्षेत्रों को निर्धारित अर्हताओं के आधार पर चयनित किया जाएगा। यह योजना केंद्र सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग के नेतृत्व में संचालित होगी तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉरपोरेशन इस योजना के लिये क्रियान्वयन एजेंसी होगी।
इसके अंतर्गत चयनित औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने हेतु अधिकतम एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ का वित्तीय

■ **राज्य सरकार ने 5 औद्योगिक हब विकसित करने के प्रस्ताव दिये**

■ **बेहतर आधारभूत ढांचे से निवेशक आकर्षित होंगे और रोजगार बढ़ेगा**

सहयोग प्रदान किया जायेगा जबकि भूमि की उपलब्धता राज्य की नोडल एजेंसी को सुनिश्चित करने होगी। भव्या योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिये राज्य सरकार ने बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं दीपा जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों को लोकेशन दिल्ली-मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलपमेंट कॉरपोरेशन इस योजना के लिये क्रियान्वयन एजेंसी होगी।
राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत चिन्हित क्षेत्रों का चयन करते समय कनेक्टिविटी, कच्चे माल की उपलब्धता, औद्योगिक भूमि की मांग,

भंडारण की सुविधा, पास में नगरीय क्षेत्र आदि कारकों का ध्यान रखा है जिससे राज्य के प्रत्येक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में इस योजना का अधिकतम लाभ लिया सके। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित इन औद्योगिक हब में अत्याधुनिक ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और सरल प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
इस योजना में केंद्र सरकार की सहभागिता से चयनित औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक क्लस्टरिंग का लाभ मिलेगा। परियोजनाओं के तेज क्रियान्वयन के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल मॉडल अपनाया जाएगा। इन परियोजनाओं के लिए चयनित लोकेशन पर समुचित भूमि उपलब्ध है जिसके परिणामस्वरूप परियोजना का क्रियान्वयन निर्बाध रूप से एवं तय समय में पूर्ण किया जा सकेगा।
बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने से निवेशक भी आकर्षित होंगे वहीं राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे एवं क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

सीएचओ भर्ती-2020 पेपर लीक का आरोपी जालौर से गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान में संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) भर्ती परीक्षा-2020 के पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने इस संगठित गिराह के सक्रिय सदस्य गणपत लाल मालवाड़ा (31) निवासी जालौर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुख्य सूत्रधार भूपेन्द्र सारण का करीबी सहयोगी रहा है और पेपर लीक की साक्ष्य में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि 10 नवंबर 2020 को आयोजित हुई सीएचओ भर्ती परीक्षा के दौरान जयपुर के निवासे रोड स्थित जागृति विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल को केंद्र बनाया गया था। जांच में सामने आया कि गिराह ने स्कूल के स्ट्रॉंग रूम से अप्रयुक्त प्रश्न-पत्रों की सील खोलकर पेपर लीक किया था। परीक्षा से मात्र दो घंटे पहले



आरोपी गणपतलाल मालवाड़ा

प्रश्न-पत्र हासिल कर उसे सॉल्वर टीम से हल करवाया गया और फिर अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया गया। इस मामले में एसओजी अब तक कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें स्कूल संचालक धीरज शर्मा, मुकेश बाना, बलवीर सुपडा, दिनेश विश्वास, भूपेन्द्र सारण और शेर सिंह

■ एसओजी इस मामले में 20 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है

मीणा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। गणपत लाल इस मामले में गिरफ्तार होने वाला 21वां आरोपी है।
पूछताछ में सामने आया है कि गणपत लाल ने न केवल भूपेन्द्र सारण को सहयोग किया, बल्कि पेपर लीक के माध्यम से अभ्यर्थियों को संगठित रूप से एकत्रित करने और उन्हें लाभ पहुंचाने में भी शामिल रहा।
एसओजी अब आरोपी से इस गिराह के अन्य नेटवर्क और वित्तीय लेन-देन के बारे में गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि गणपत से पूछताछ में भर्ती परीक्षाओं में सक्रिय अन्य पूर्णों के बारे में भी महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं।

कांग्रेस ने रिफाइनरी में कई घोटाले किए : मुख्यमंत्री

चुरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने देशहित से जुड़े हर मुद्दे का विरोध किया है। इनके नेता महिला आरक्षण का विरोध और सेना का अपमान करते हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम से महिलाओं को आरक्षण मिले, इनका काम ही विरोध करना है। उन्होंने कहा कि धारा 370 का कांग्रेस ने विरोध किया।
शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग वे ही हैं, जो शेखावाटी के लिए हमेशा यमुना के जल का सपना दिखाते थे। चुनाव आते थे तब झूठ के पुल बनाते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने रिफाइनरी में कई तरह के घोटाले और जमीनों के घोटाले किये। इनमें कांग्रेस के लोग कैसे काम कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इनका हिसाब लेना चाहिए।

जवाहर सर्किल के पास 13 बीघा भूमि मामले में जेडीए की अपील मंजूर

राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 51 वर्ष पहले अवाप्त जमीन के मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण को राहत दी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 51 वर्ष पहले अवाप्त जमीन के मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण को राहत दी है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अवाप्तशुदा जमीन के बदले 25 प्रतिशत जमीन देने के फैसले को खारिज कर दिया। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश जेडीए की अपील को मंजूर करते हुए दिए।
जेडीए की ओर से अपील में अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जिस मामले में जमीन के बदले 25 प्रतिशत विकसित

से पहले की है, इसलिए एकलपीठ का आदेश सही है। न काश्तकारों को मुआवजा मिला है और न ही कब्जा लिया गया है। इस मामले में अवाप्तशुदा जमीन के बदले 25 प्रतिशत विकसित जमीन देने की राज्य सरकार की गारंटीबद्धता लागू होती है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जेडीए की अपील को मंजूर करते हुए एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया है।
मामले के अनुसार अवाप्त को काश्तकारों ने वर्ष 1974 में याचिका के जरिए चुनौती दी, जिसे हाईकोर्ट ने मई 1975 में खारिज कर दिया। साल 1975 में फिर याचिका दायर की गई, जो मार्च 1978 में निस्तारित कर दी गई।
विवಾದ अदालत में लंबित होने के कारण जेडीए ने 1979 में मुआवजा राशि कोर्ट में जमा कराया।
साल 2010 में काश्तकार रणजीत सिंह की ओर से याचिका दायर की गई, जो अगस्त 2012 में खारिज कर दी गई। इसके खिलाफ पेश एसएलपी भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद कई बार अलग-अलग याचिका दायर हुईं, जो खारिज हुईं।
वहीं साल 2023 में फिर याचिका दायर हुई, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने मार्च 2026 में काश्तकार के परिवार को 20 प्रतिशत आवासीय व 5 प्रतिशत वाणिज्यिक विकसित जमीन देने का आदेश दिया।

बी.सी.आर. चुनाव में अव्यवस्था के बाद हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट पोलिंग बूथ का मतदान रद्द

इन दोनों जगहों पर जल्द ही नई चुनाव तिथि घोषित की जाएगी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। प्रदेश के अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के 23 सदस्यों के चुनाव बुधवार को प्रदेशभर में आयोजित हुए। हालांकि इस दौरान जयपुर में हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट में पोलिंग बूथ पर हुई अव्यवस्था और पारदर्शिता के अभाव के चलते मतदान प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। यहां जल्दी ही नई चुनाव तिथि घोषित की जाएगी।
हाईकोर्ट जयपुर के पोलिंग ऑफिसर अधिवक्ता बसंत सिंह छावा ने बताया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा था और इसमें अव्यवस्था सामने आ रही थी। इन कारणों से ही हाईकोर्ट में बीसीआर चुनाव रद्द किया गया है। हाईकोर्ट प्रदेशभर में बीसीआर चुनाव



बार कौंसिल के चुनाव में बुधवार को अव्यवस्था के बाद अधिवक्ताओं ने हंगामा कर दिया।

का सबसे बड़ा पोलिंग बूथ है और यहां पर 14 हजार 781 मतदाता हैं। वहीं बनीपार्क स्थित सेशन कोर्ट में भी चुनाव मतदान की सही व्यवस्था नहीं होने,

मतदान निरस्त करने का निर्णय लिया। सेशन कोर्ट में मतदाताओं की संख्या 5439 है और यहाँ पर भी बारूक के 57 मतों के लिए भी मतदान होना था। हाईकोर्ट बूथ पर मतदान करीब 50 मिनट देरी से शुरू हुआ और हाईकोर्ट के रिटायर जस्टिस वीएस दवे ने पहला मत दिया, लेकिन इसके बाद ही मतदान प्रक्रिया में अव्यवस्था होना और पारदर्शिता नहीं होने के कारण चुनाव को रद्द कर दिया। चुनाव सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस सुधांशु धुलिया की निगरानी में हो रहे हैं और राजस्थान में चुनाव कराने की जिम्मेदारी दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जे आर मिश्रा की तीन सदस्यीय कमेटी के पास है। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस मनोज गर्ग राज्य स्तरीय ऑब्जर्वर बनाए गए हैं।

एआई से बना रहे थे न्यूज चैनल का फर्जी वीडियो

जयपुर पुलिस ने गिराह का पर्दाफाश कर चार आरोपियों को दबोचा

जयपुर। तकनीकी के दुरुपयोग से समाज में भ्रम फैलाने वाली के खिलाफ जयपुर साइबर पुलिस ने हाईकोर्ट के स्ट्राइक की है। पुलिस ने न्यूज चैनल के लोग और एंकर की आवाज का इस्तेमाल कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित फर्जी वीडियो बनाने वाले गिराह का भंडाफोड़ करते हुए चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि 18 अप्रैल को परिवारी सत्यनारायण शर्मा ने मामला दर्ज कराया था कि फेसबुक पर एक एआई जनित रील वायरल की जा रही थी, जिसमें न्यूज चैनल के स्टूडियो बैकग्राउंड और एंकर की आवाज को एडिट कर भ्रामक जानकारी परोसी गई थी। लोग इसे सच मानकर धड़ल्ले से शेयर कर रहे थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएफएस और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।
अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर डॉ. अजय सिंह और पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजेश राज के सुपरविजन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर फर्जी वीडियो के मूल स्रोत की पहचान की। पुलिस ने दक्षिण देकर इस साक्ष्य में शामिल चार मुख्य किरदार बिलाल शांमिल (27) निवासी भोपाल मध्य प्रदेश, इनाम अहमद (29) निवासी भोपाल मध्य प्रदेश, निखिल प्रजापत (22) निवासी भोपाल मध्य प्रदेश और अमृता धुमाल (37) निवासी पंजाब को गिरफ्तार किया है।
जांच में सामने आया कि आरोपियों ने हाई-टेक, एआई टूल्स का उपयोग कर न्यूज क्लिप को एडिट किया। उन्होंने एंकर को फेसबुक पर एआई जनित रील वायरल की जा रही थी, जिसमें न्यूज चैनल के स्टूडियो बैकग्राउंड और एंकर की आवाज को एडिट कर भ्रामक जानकारी परोसी गई थी। लोग इसे सच मानकर धड़ल्ले से शेयर कर रहे थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएफएस और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।
अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर डॉ. अजय सिंह और पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजेश राज के सुपरविजन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर फर्जी वीडियो के मूल स्रोत की पहचान की। पुलिस ने दक्षिण देकर इस साक्ष्य में शामिल चार मुख्य किरदार बिलाल शांमिल (27) निवासी भोपाल मध्य प्रदेश, इनाम अहमद (29) निवासी भोपाल मध्य प्रदेश, निखिल प्रजापत (22) निवासी भोपाल मध्य प्रदेश और अमृता धुमाल (37) निवासी पंजाब को गिरफ्तार किया है।
जांच में सामने आया कि आरोपियों ने हाई-टेक, एआई टूल्स का उपयोग कर न्यूज क्लिप को एडिट किया। उन्होंने एंकर को फेसबुक पर एआई जनित रील वायरल की जा रही थी, जिसमें न्यूज चैनल के स्टूडियो बैकग्राउंड और एंकर की आवाज को एडिट कर भ्रामक जानकारी परोसी गई थी। लोग इसे सच मानकर धड़ल्ले से शेयर कर रहे थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएफएस और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

कौशल शिक्षा का उपयोग राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए हो : हरिभाऊ बागडे

नैतिक मूल्यों की शिक्षा से भौतिक विकास की गुणवत्ता में वृद्धि होती है : राज्यपाल

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि कौशल शिक्षा का उपयोग राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसके पास अच्छा कौशल है, उसे सभी स्थानों पर काम मिलता है, वह कभी भूखा नहीं रहता। उन्होंने कौशल शिक्षा के साथ विश्वविद्यालयों में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा से भौतिक विकास की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। राज्यपाल बागडे बुधवार को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष दीक्षांत समारोह आयोजक रूप से किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह भले ही छोटे स्तर पर ही हो, परंतु नियमित होना चाहिए। जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में पढ़ते

■ 'अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा को बदल कर गुलाम मानसिकता की शिक्षा प्रदान की'

रोके जाने की शिक्षा दी जाए। उन्होंने इसके लिए शिक्षकों को स्वयं को अपडेट रखते हुए शिक्षा का प्रभावी विकास करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में अच्छा नागरिक बनाने के साथ आदर्श आचरण पर विशेष जोर दिया गया है।
राज्यपाल ने कहा कि आजादी से पहले देश में आठ लाख से अधिक गुरुकुल थे। इनमें सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजों ने भारत की इस शिक्षा को बदल कर गुलाम मानसिकता की शिक्षा प्रदान की। बागडे ने विश्वकर्मा को देवताओं के शिल्पकार बताते हुए कहा कि वह ब्राह्मण के प्रथम ईजांनियर थे। उन्होंने

एम. विश्वेश्वरैया को याद करते हुए उनके अभियांत्रिकी कौशल और समय पाबंदी से सीख लेने का आनंद बताया। उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल विभाग मंत्री जनेल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जो कुछ विद्यार्थी सीखे उसका दायरा सीमित नहीं रहे।
उन्होंने विद्यार्थियों को सृजनात्मक रहने, निरंतर दूसरों से सीखते हुए अपने कौशल से दुनिया को बदलने, विकसित किए जाने का आह्वान किया। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. देवस्वरूप ने सभी का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा कौशल विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। इससे पहले विश्वविद्यालय के बारे में फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल ने इससे पहले विद्यार्थियों को डिग्री और पदक प्रदान किए।

परशुराम शोभायात्रा को लेकर विशेष व्यवस्था

जयपुर। भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में 23 अप्रैल 2026 को शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान शहर के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक यातायात व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। पुलिस प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शोभायात्रा सायं 6:30 बजे चंद्रपोख क्षेत्र के जलेब चौक से रवाना होकर हवामहल बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, बापू बाजार, न्यू गेट, चौडा रास्ता, त्रिपोलिया गेट और त्रिपोलिया बाजार होते हुए छोटी चौपड़ पहुंचकर विसर्जित होगी।
यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। शोभायात्रा मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही सायंकाल 4 बजे से सांगानेरी गेट, घाटगेट चौराहा, घोबीघाट, रामगंज मोड और संजय सर्किल से मिनी व सिटी बसों का संचालन परकोटा क्षेत्र में बंद रहेगा।
हवामहल बाजार, जौहरी बाजार, बापू बाजार, चौडा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार और गंगौरी बाजार में भी शाम 4 बजे से सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन और पार्किंग निषेध रहेगी। विभिन्न प्रमुख मार्गों जैसे सुधाष चौक, बड़ी चौपड़, रामगंज चौपड़, सांगानेरी गेट और त्रिपोलिया की ओर आने वाले यातायात को डाइवर्ट कर वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा। इसके अलावा न्यू गेट, रामनिवास बाग चौराहा, नेहरू बाजार और त्रिपोलिया गेट-पाईंट से चौडा रास्ता की ओर किसी भी प्रकार के वाहन नहीं जाने दिए जाएंगे। छोटी चौपड़ और त्रिपोलिया क्षेत्र में भी यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

मुख्यमंत्री ने ओसियां में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाएं और समृद्ध बनें

जोधपुर/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास का रोडमैप बनाया है, जिसके अनुरूप पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य किया जा रहा है। जनकल्याण के जो भी वादें किए हैं, उन्हें पूरा करते हुए हर क्षेत्र को समग्र विकास की उगांत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-विकसित राजस्थान के लक्ष्य के क्रम में युवा, महिला, किसान और मजदूर का कल्याण सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जोधपुर के ओसियां में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।



ओसियां में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सड़क सहित विभिन्न क्षेत्रों के 416 करोड़ रुपये से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने ओसियां उपखण्ड मुख्यालय पर खेल स्टेडियम के निर्माण के साथ ही नेतरा और पिचकीबेरा में 33 केवी के जीएसएस के स्थापना की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाएं और समृद्ध बनें। इसी कड़ी में

राज्य सरकार जयपुर में 23 से 25 मई तक ग्राम-2026 का आयोजन भी कर रही है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 19 लाख पॉलिसी जारी की गई है तथा 6 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक के क्लेम वितरित किए हैं। वहीं, पीएम कुसुम योजना के तहत 65 हजार सोलर पंप सेट स्थापित करने के लिए 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है। उन्होंने

राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लाभों और उपलब्धियों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंद्रिया गांधी नहर एवं गंगानहर का सड़कीकरण, देवास परियोजना का विस्तार, सोम-कमला-अंबा एवं ब्राह्मणी नदी से संबंधित परियोजनाओं को साकार करने का काम रही है। जोधपुर, पाली

और सिरोंही सहित सभी क्षेत्रों को पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है।

सीएम शर्मा ने कहा कि पेपरलीक के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए 400 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पचपदरा स्थित एचपीसीएल

■ **सीएम भजनलाल शर्मा ने ओसियां उपखण्ड मुख्यालय पर खेल स्टेडियम के निर्माण के साथ ही नेतरा और पिचकीबेरा में 33 केवी के जीएसएस के स्थापना की घोषणा भी की**

रिफाइनरी औद्योगिक विकास की प्रतीक है। एचपीसीएल रिफाइनरी में उद्घाटन से पूर्व दुर्घटनापूर्ण घटना हुई। इस अवसर पर शर्मा ने विधायक भैराम सिरोल के माता-पिता की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने ओसियां विकास दर्शन पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के.के. विश्वासे, सांसद पी.पी. चौधरी, राजेंद्र गहलोट, विधायक बाबू सिंह राठौड़, पब्लिक मन्थन-ई, अर्जुन लाल, देवेन्द्र जोशी, जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह विश्वासे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, संत एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

खेतड़ी में सड़क किनारे संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला

खेतड़ी, (निर्स)। पचेरीकलां थाना के सड़क गांव के पास सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना को लेकर ग्रामीणों ने युवक की हत्या कर शव सड़क किनारे डालने का आरोप लगाया है। घटना को लेकर पुलिस ने शव को बुहाना के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी के अनुसार सड़क निवासी विक्रम सिंह पुत्र रघुवीर यादव का शव बुधवार को पचेरी-सहड़ सड़क पर भाजरी के पास संदिग्ध अवस्था में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस फिलहाल मामले को एक्सडीट और मर्डर दोनों एंगल से जांच रही है। मृतक के ताऊ के बेटे कृष्ण कुमार ने बताया कि विक्रम सिंह मंगलवार शाम को गुराम से अपने गांव सहड़ लौट रहा था। उसके पास बस की टिकट भी मिली है, जिससे उसके यात्रा करने की पुष्टि होती है। रातभर घर नहीं पहुंचने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान पुलिस को और से सूचना मिली कि पचेरी-सहड़ रोड पर एक युवक का शव

■ **ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि मामले को एक्सडीट बताकर परिजनों को गुमराह किया जा रहा है, पुलिस ने जांच शुरू की**

मिला है, जो विक्रम सिंह का है। घटना की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे तथा शव की शिनाख्त की। उनका कहना है कि विक्रम की मौत सामान्य हादसा नहीं लग रही, बल्कि किसी साजिश के तहत उसे मारा गया है। परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटना की खबर फैलते ही सहड़ गांव में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण बुहाना मोर्चरी के बाहर एकत्रित हो गए। पुलिस ने परिजनों को शिकायत देने के लिए कहा है और पोस्टमार्टम करवाकर मौत के कारणों का खुलासा करने की बात कही है।

ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि मामले को एक्सडीट बताकर परिजनों को गुमराह किया जा रहा है। उनका कहना है कि मृतक के शरीर पर

चोट के स्पष्ट निशान हैं। वहीं डेड बॉडी के पास खून के धब्बे भी मिले हैं। ग्रामीणों के अनुसार मृतक के सिर पर किसी इथिथारमुला वस्तु से वार किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि यह मामला साधारण सड़क हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। मृतक विक्रम तीन भाई हैं एक भाई की पहले मौत हो चुकी है तथा एक भाई सिंह सेना में है। मृतक के दो बच्चे आयुष 12 साल, आरव 9 साल हैं। वह गुरुग्राम में ड्राइवर की नौकरी करता था। इस संबंध में थानाधिकारी बनवारीलाल यादव ने बताया कि मृतक के ताऊ के लड़के की ओर से दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ओ की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है।

भूलवश कीटनाशक सेवन से युवती की मौत

जोधपुर, (कास)। निकटवर्ती मथानिया के रामपुरा भाटियान गांव में एक युवती ने भूलवश से कीटनाशक सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी उपचार के बीच मौत हो गई। उसके

बाई की तरफ से पुलिस में मर्ग की रिपोर्ट दी गई। मथानिया पुलिस ने बताया कि मूलतः नागौरी बेरा मंडोर हाल डालाबेरा रामपुरा भाटियान निवासी महेंद्र बुद्ध संतोकराम ने रिपोर्ट दी है। इसमें बताया

कि उसकी बहन 19 वर्षीय संजु ने 18 अप्रैल को खेत पर काम करने के समय भूल से कीटनाशक का सेवन कर लिया था। इस पर उसकी तबीयत बिगड़ गई। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, अब मौत हो गई।

जोधपुर के तीन युवकों से झुंझुनू के दो युवकों ने लाखों की धोखाधड़ी की

जोधपुर, (कास)। शहर के रातानाडा स्थित सुभाष चौक में रहने वाले तीन युवकों से 25 लाख के करीब का फ्रॉड हो गया। झुंझुनू के दो युवकों ने उन्हें झांसे में लेकर म्यूच्युअल फंड में इन्वेस्टमेंट के नाम पर अपनी धोखाधड़ी का शिकार बनाया। 16 महिने बीतने के बाद भी ना तो मुनाफा मिला और ना ही दी गई राशि लौटाई गई। आरोपियों ने अब अपना फोन भी बंद कर दिया और ठिकाना भी बदल लिया है। रातानाडा पुलिस ने कोर्ट से मिले इस्तगसे पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच आरंभ की है।

रातानाडा पुलिस ने बताया कि न्यू

■ **म्यूच्युअल फंड में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 25 लाख की ठगी की**

■ **16 महिने बीतने के बाद भी ना तो मुनाफा मिला और ना ही दी गई राशि लौटाई**

रेलवे कॉलोनी, सुभाष चौक निवासी प्रमोद जटवाल, रामावतार एवं अश्विनी कुमार की तरफ से एक संयुक्त परिवार

दिया गया। इसमें बताया कि उनकी पहचान झुंझुनू के बासरी निवासी गौरव शर्मा से वर्ष 2022 से थी। गौरव शर्मा ने बाद में उन्हें झुंझुनू के पुजारियों का मोहल्ला निवासी ललित शर्मा से मिलाया था। ललित शर्मा ने खुद को एक बड़ी कंपनी में होना बताकर उनसे इन्वेस्टमेंट करने को कहा। उन्हें रूपए डबल करने का आश्वासन दिया गया। इस पर बाद में तीनों ने मिलकर ललित शर्मा और गौरव शर्मा के कहे अनुसार म्यूच्युअल इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया। रिपोर्ट के अनुसार प्रमोद जटवाल ने 13 नवंबर से 17 नवंबर 2024 फिर 1 अक्टूबर 2025 से

11 अक्टूबर 2025 तक 9 लाख रूपए इन्वेस्ट किए। जोकि फोन पे, गुगल और अन्य ऑन लाइन साधन से दिए गए। वहीं रामावतार की तरफ से 16 जून 2025 से 8 नवंबर 2025 तक 13 लाख रूपए दिए गए। साथ ही अश्विनी कुमार ने 4.38 लाख रूपए इन्वेस्ट किए। मगर इस्के बाद आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया। 16 महिने गुजरने के बाद भी जमा कराई वापिस नहीं मिली। साथ ही मुनाफा भी नहीं दिया गया। आरोपियों ने अपना ठिकाना भी बदल दिया है। पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच आरंभ की है।

पिता-पुत्र को एसयूवी ने टक्कर मारी, मौत

जोधपुर, (कास)। जिले के चामु क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत लोडता हिरदासेत में बस का इंतजार कर रहे पिता-पुत्र को एक तेज रफ्तार एसयूवी ने कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर चामु पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई की।

पुलिस ने बताया कि कुनाराम (50) पुत्र जोगाराम और उसके 13 वर्षीय पुत्र जसाराम की मौत हुई है। दोनों देचू जाने के लिए सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान देवातु से देचू की ओर जा रही एक बावत की एसयूवी तेज गति से अनियंत्रित हो गई और पलटते हुए सड़क किनारे खड़े पिता-पुत्र को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही चामु पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। वहीं, हादसे में एसयूवी में सवार कुछ लोग भी घायल हुए हैं।

जोधपुर : जेएनवीयू में बकाया पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी

पेंशनर्स ने चार माह की बकाया पेंशन के भुगतान की मांग की

■ **जेएनवीयू में पेंशनर्स ने बकाया पेंशन के भुगतान की मांग को लेकर पेंशन सोसाइटी के बैनर तले केंद्रीय कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विवि प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज के घरने में उन अभावग्रस्त अशिक्षणक वरिष्ठ कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से कमना संभाली जिन्होंने या तो अपने परिजनों को पेंशन न मिलने के कारण खो दिया या जो घनाभाव के कारण भूखें मरने के कगार पर हैं। पेंशनर्स ने चेतावनी दी कि पेंशन का भुगतान नहीं हो जाता या विश्वविद्यालय लिखित में बकाया पेंशन भुगतान की तारीख नहीं बताएगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से स्पष्ट कहा कि अब केवल मौखिक आश्वासन नहीं, बल्कि**

■ **चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा**

लिखित में पेंशन भुगतान की गारंटी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए पेंशनधारकों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन बकाया पेंशन का भुगतान न करके अन्याय का परिचय दे रहा है, जो हमें किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने बताया कि अधिकांश कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति इतनी दरनीय हो चुकी है कि वे अपने परिवार का न केवल भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, बल्कि उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा भी नहीं

दे पा रहे हैं। ऐसे ही अनेक कर्मचारियों ने अपनी व्यथा सबके समक्ष व्यक्त की। जिनमें बाबूलाल सियोटा, अमर सिंह, प्रदीप कुमार शर्मा, नूरजहां, रविन्द्र सिंह शेखावत, मोहम्मद शरीफ, जेटू सिंह, तथा परमेश्वर सिंह चौहान आदि थे। आज प्रदर्शन में सम्मिलित होने वालों में पूर्व कुलपति प्रो. भंवर सिंह राजपुत्रोहित, प्रो. कैलाशनाथ व्यास, प्रो. बीना त्रिपाठी, प्रो. पीके बनर्जी, राकेश मेहता, राधेश्याम शर्मा, दिनेश रामावत, गोपाल चौहान आदि के साथ साथ अनेक वरिष्ठ जन भी उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए संयोजक अशोक व्यास और अध्यक्ष प्रोफेसर राम निवास शर्मा ने कहा कि जब तक हमारी पेंशन का भुगतान नहीं हो जाता या विश्वविद्यालय लिखित में बकाया पेंशन भुगतान की तारीख नहीं बताएगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।

अलवर : गर्मी में पानी का संकट गहराया, घरों में पांच दिन से पानी की सप्लाई

अलवर, (निर्स)। गर्मी के साथ ही पानी का संकट भी गहराने लगा है। अलवर के वार्ड 12 में 4 से 5 दिनों में पानी की सप्लाई होती है। पेयजल समस्या से परेशान लोगों ने लादिया फील्ड सप्लाई प्लांट पर जाकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को घेराव कर दिया। नौबत ये आई गई कि पुलिस जान्ना बुलाना पड़ा। पानी की सप्लाई होने के बाद ही लोग शांत हुए।

प्रदर्शन के दौरान अखैरुा थाने के थाना प्रभारी महेश तिवारी ने एक महिला से कहा 'मैंने आपको देख रखा है।' गौतलब है कि पानी को लेकर पहले भी प्रदर्शन होते आए हैं, जिसमें महिला और थाना प्रभारी का पहले भी आमना-सामना हुआ है। वहीं जेईएन ने दो लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पानी संकट का ये मामला वार्ड 12 के होली ऊपर

■ **पेयजल समस्या से परेशान लोगों ने लादिया फील्ड सप्लाई प्लांट पर जाकर प्रदर्शन किया**

व कुम्हार पाड़ी सहित आस-पास के मोहल्ले का है। पानी की किल्लत को लेकर आज लादिया फील्ड सप्लाई प्लांट पर विरोध-प्रदर्शन किया गया था। जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों से लोगों की बहस हुई। लोगों ने अधिकारियों का घेराव कर दिया।

वार्ड में रहने वाले गौरव शर्मा ने बताया कि लादिया फील्ड से वार्ड 12 और 19 पानी की सप्लाई होती है। वार्ड 12 में पानी की हमेशा किल्लत बनी रहती है। वार्ड 12 के होली ऊपर, कुम्हार पाड़ी सहित अन्य हिस्सों में 4

से 5 दिन में पानी आता है। वह भी पूरा नहीं आ रहा है। इस कारण मंगलवार सुबह लोग लादिया पानी की सप्लाई प्लांट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। पुलिस के आने के बाद जलदाय विभाग ने वार्ड 12 के क्षेत्र में पानी की सप्लाई की। उसके बाद मामला शांत हुआ।

महेश कुमार ने बताया कि वार्ड 19 में पानी की सप्लाई ठीक होती है। वहां पानी की किल्लत नहीं रहती है। वार्ड 18 पूर्व महापौर घनश्याम गुजर का वार्ड है। वहीं वार्ड 12 भी उससे लगता क्षेत्र है। यहां पानी की सप्लाई कम होती है। पहले दो दिन में करीब एक घंटे से ज्यादा सप्लाई हो जाती थी। अब तो 3 दिन में तो कभी 5 दिन में पानी आता है। वह भी पूरा नहीं आता है। घरों में पानी नहीं आने पर लादिया प्लांट पर आकर विरोध किया। हंगामे और घेराव को देखते हुए अधिकारियों ने एडीएम को सूचना देकर पुलिस जान्ना मांगा।

इसके बाद अखैरुा थाना प्रभारी महेश तिवारी जाबते के साथ पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों के बीच समझाइश की। वार्ड के 12 के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई की गई। आगे तय समय पर सप्लाई करने का आश्वासन दिया गया। तब लोग माने।

ईएन सुनील कुमार यादव ने अखैरुा थाने में राजकार्य में बाधा पहुंचाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया कि राजकार्य सत बजे के आस-पास पानी की सप्लाई दी जाती थी। उससे पहले ही 6-45 बजे वार्ड 12 में रहने वाले गौरव शर्मा और बिजेंद्र गुजर सहित अन्य लोगों ने लादिया पंप हाउस पर ताला लगा दिया। उन्होंने पंप हाउस से पानी की सप्लाई नहीं होने दी और राजकार्य में बाधा उत्पन्न की। एडीएम को सूचना देकर पुलिस जान्ना मांगा गया। साढ़े आठ बजे के बाद पानी की सप्लाई की जा सकी।

महिला आरक्षण को अटकाने की प्रक्रिया को कांग्रेस व सहयोगी दलों ने जारी रखा : डॉ. निमिषा

करौली, (निर्स)। करौली में बुधवार को भाजपा कार्यालय पर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर निमिषा गौर ने प्रेस वार्ता में कहा कि चार दशक से महिला आरक्षण को अटकाने, लटकाने एवं भटकाने की प्रक्रिया को कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दलों ने जारी रखा। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को केंद्र सरकार ने लोकसभा में तीन विधेयक पेश

■ **नारी शक्ति वंदन अधिनियम की क्रियान्वयन में बाधा डालने वाले विपक्ष के विरुद्ध महिलाओ में आक्रोश : डॉ. निमिषा गौर**

कि, जिसमें संविधान (एक सौ इकतालीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 एवं केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किए गए। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रभाव बनना है कि महिलाओं के लिए आरक्षण 2026 के बाद आयोजित होने वाली जनगणना के बाद परिसीमन के आधार पर लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार जनगणना और परिसीमन की प्रतीक्षा करती, तो जनगणना और उन्हे बाद परिसीमन की अवधि में समय लगाने के कारण महिलाएं 2029 के आम चुनावों में भी



करौली में भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर निमिषा गौर ने प्रेस वार्ता की।

33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाती। अगर ये बिल पास हो जाता, तो महिलाएं वर्ष 2029 के आम चुनावों में ही लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त करने में सक्षम हो पाती। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता डॉ. निमिषा गौर ने कहा कि परिसीमन का अर्थ है निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को अंतिम रूप देना। महिला आरक्षण लागू करने के लिए यह अनिवार्य है। 1976 में लोकसभा में सौंटी की सीमा 550 निर्धारित की गई थी। 1971 में भारत की जनसंख्या 54 करोड़ थी, परंतु आज यह संख्या 140 करोड़ है। इसलिए, लोकसभा में सौंटी की संख्या बढ़कर 850 करना महत्वपूर्ण है। परिसीमन आयोग अधिनियम में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया था। मौजूदा कानूनी ढांचा बरकरार है, और आयोग की किसी भी

सिफारिश के लिए संसदीय अनुमोदन और राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होगी। सौंटी में समान रूप से 50 प्रतिशत की वृद्धि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुपात बनाए रखेगी। यह प्रस्ताव आनुपातिक विस्तार दृष्टिकोण पर आधारित था। वर्तमान 543 सौंटी पर इस सिद्धांत को लागू करने से लगभग 815 सौंटी हो जाएंगी। इसलिए, लोकसभा में सौंटी की ऊपरी सीमा को वर्तमान 550 सौंटी से बढ़ाकर 850 कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों को प्रतिनिधित्व में किसी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उनका कुल हिस्सा स्थिर रहेगा। आरक्षण लागू करने के लिए सौंटी के परिसीमन की आवश्यकता होती है। परिसीमन एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया है और इसे पूरा

करने में लगभग दो साल लगते हैं। इसलिए, महिला आरक्षण लागू करने के लिए ये विधेयक (परिसीमन विधेयक सहित) संसद में लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के लिए कानूनी और संवैधानिक ढांचा स्थापित करने के लिए विधेयक को 2023 में पेश और पारित किया गया था। इसलिए इन क्षेत्रों में महिला आरक्षण लागू करने के लिए विशिष्ट संशोधनों की आवश्यकता थी, जिसके लिए एक अलग विधेयक आवश्यक हो गया।

प्रेस वार्ता के दौरान करौली धौलपुर सांसद प्रत्याशी ईंदू देवी जाटव, क्षेत्रीय विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, योगेश शर्मा, सुरेश शुक्ला, पुष्पेंद्र, अजय सिंह राजपुत्र, विद्या वैष्णव, आदित्य शर्मा, गोपाल शर्मा, जितेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंघल आदि उपस्थित रहे।

कैला माता के श्रद्धालुओं की बस में आग लगी, हादसा टला

कैलादेवी/करौली, (निर्स)। आस्थाधाम कैलादेवी में बुधवार दोपहर कैला माता के दर्शन करने आए दर्शनार्थियों की एक डबल डेकर एम (पीटीआई) की सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इन शिक्षकों ने वर्ष 2022 की जांच के दौरान अभ्यर्थियों की फर्जी डिग्रियां और अन्य अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जोशी ने आगे बताया कि विभागीय आदेशों के तहत इन आठ तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इन शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश की जेएस यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की थी।

इस दौरान आग की लपटों से धूप का गुबार उठने लगा। धूप के गुबार को देखकर मौके पर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर कैला देवी धानाधिकारी रामवतार मीना मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी मीना ने बताया कि बस का ड्राइवर खाना खाने गया था तथा दर्शनार्थी मंदिर दर्शन के लिए गये थे। गनीमत यह रही की डबल डेकर एम की बस से यात्री दर्शन करने के लिए मां के

मंदिर चले गए जिससे बस खाली होने के कारण कोई अनहोनी घटना नहीं हुई। दर्शनार्थियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कानपुर उत्तर प्रदेश से एसी बस मंगलवार शाम सात बजे कैलादेवी के लिए रवाना हुई थी। बस में करीब 30-35 यात्री दर्शन के लिए आए थे। अज्ञात कारणों से बस में अचानक आग लग गयी। हालांकि स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का पूरा प्रयास किया लेकिन वह नाकाफी साबित हुआ।

बंद घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी

धौलपुर, (निर्स)। धौलपुर निहालगंज थाना क्षेत्र की अशोक बिहार कॉलोनी में देर रात एक बंद मकान के कमरे में भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त मकान मालिक अशोक शर्मा परिवार के सभी सदस्यों के साथ शादी समारोह में गए हुए थे। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते घर में रखा लाखों रूपए का कीमती सामान जलकर खाक हो गया। फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और घर में रखी नकदी सब आग की भेंट चढ़ गए। आसपास के लोगों ने धुआं उठता देख पुलिस और दमकल को सूचना दी।

डूंगरपुर में फर्जी डिग्री वाले आठ शारीरिक शिक्षक बर्खास्त

2022 की भर्ती में फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल की थी

डूंगरपुर, (निर्स)। फर्जी डिग्री के मामले में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने डूंगरपुर जिले के आठ शारीरिक शिक्षकों (पीटीआई) को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इन शिक्षकों ने वर्ष 2022 की जांच के दौरान अभ्यर्थियों की फर्जी डिग्रियां और अन्य अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जोशी ने आगे बताया कि विभागीय आदेशों के तहत इन आठ तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इन शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश की जेएस यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की थी।

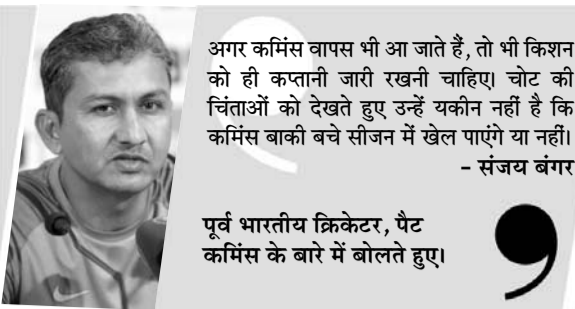
जोशी ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित पीटीआई-शिक्षक भर्ती परीक्षा में आचार अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने का मामला सामने आया था। जांच के दौरान अभ्यर्थियों की फर्जी डिग्रियां और अन्य अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जोशी ने आगे बताया कि विभागीय आदेशों के तहत इन आठ तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इन शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश की जेएस यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की थी।

डेयरी के पूर्व सचिव की हत्या के आरोपी को उम्रकैद

अजमेर, (कास)। डेढ़ वर्ष पूर्व सरस डेयरी समिति के पूर्व सचिव की हत्या मामले में बुधवार को अजमेर की एडीजे-4 कोर्ट के न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा और 35 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में पीड़ित की ओर से पैरवी सरकारी वकील गुलाम नजमी फारूकी ने की थी। सरकारी एडवोकेट गुलाम नजमी फारूकी ने बताया कि 20 नवंबर 2024 को सरस डेयरी समिति के पूर्व सचिव के किशनलाल की दिनहाड़े हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने किशनलाल के चेहरे पर मिर्ची स्प्रे कर चाकू से हमला किया था। मामले के सूचना पर रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। वहीं घटना किशनलाल की दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई थी। किशनलाल के भाई हंसराज की शिकायत पर रामगंज थाना

पुलिस ने आरोपी दिलीप चौधरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। इसके बाद से कोर्ट में दायल चल रही थी। हमलावर चाकू लेकर सेक्रेटरी किशनलाल के ऑफिस में घुसा और कुर्सी पर बैठे किशनलाल के चेहरे पर मिर्ची स्प्रे छिड़ककर चाकू से हमला किया और भागने लगा। इस पर किशनलाल कुर्सी लेकर उसके पीछे दौड़े थे। बाहर जाकर वो सड़क पर गिर गए थे।

सरकारी वकील फारूकी ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 27 गवाह और 60 दस्तावेज पेश किए गए। साथ ही चाकू सहित अन्य सबूत कोर्ट में पेश किए थे। इसके आधार पर एडीजे-4 कोर्ट के न्यायाधीश रितु मीणा ने बुधवार को दोषी दिलीप चौधरी को उम्रकैद की सजा सुनाई।



अगर कमिंस वापस भी आ जाते हैं, तो भी किशन को ही कप्तानी जारी रखनी चाहिए। चोट की चिंताओं को देखते हुए उन्हें यकीन नहीं है कि कमिंस बाकी बचे सीजन में खेल पाएंगे या नहीं।
- संजय बंगर

पूर्व भारतीय क्रिकेटर, पेट कमिंस के बारे में बोलते हुए।



खेल जगत

आज का खिलाड़ी



हेनरिक क्लासेन

सनराइजर्स हैदराबाद के तूफानी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में इतिहास रच दिया है। दरअसल, हेनरिक आईपीएल इतिहास में सबसे कम पारियों में 100 छक्के जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इस एलिट लिस्ट में उनसे ऊपर सिर्फ दो खिलाड़ी क्रिस

क्या आप जानते हैं? ... श्रीलंका के खिलाफ जुलाई 2024 में 77वीं द्विपक्षीय टी-20 सीरीज जीतकर भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

राष्ट्र उदयपुर, 23 अप्रैल, 2026

5

राजस्थान रॉयल्स जीत की पट्टी पर लौटी, लखनऊ ने लगातार चौथा मुकाबला गंवाया

लखनऊ, 22 अप्रैल। राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग मैच में बुधवार को लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रन से शिकस्त दी। राजस्थान रॉयल्स ने छह विकेट पर 159 रन बनाने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी को 18 ओवर में 119 रन पर समेट दिया। सुपर जायंट्स के लिए मिचेल मार्श ने 41 गेंदों में सबसे ज्यादा 55 रन का योगदान दिया। उन्हें हालांकि दूसरे छोर से किसी और का साथ नहीं मिला। रॉयल्स के लिए जोफ्रा आचर ने तीन, जबकि नांदे बंगर और ब्रुजेश शर्मा ने दो-दो विकेट लिए। लखनऊ को आईपीएल 2026 में पांचवीं हार है, जबकि राजस्थान ने जारी सीजन में 5वां मुकाबला जीता है। आईट्स टेबल में राजस्थान की टीम 10 अंक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स 4 अंक के साथ नौवें स्थान पर है।

मार्श ने खेती दमदार पारी

160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम के तीन बल्लेबाज पावरप्ले में बिना खाता खोले आउट हुए। आयुष बडोनी रन आउट हुए। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत खराब शॉट खेलकर पेवेलियन



लौटी। अनुभवी बल्लेबाज एडन मार्करम का बल्ला नहीं चला और वह भी खाता नहीं खोल सके। इसके बाद पूरन ने मार्श के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 41 गेंद में 43 रन जोड़े। निकोलस पूरन 25 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हुए। हिम्मत सिंह ने 15 गेंद में 15 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने सबसे ज्यादा रन बनाए। मार्श ने 41 गेंद में 55 रन बनाए।

इससे पहले मोहम्मद शमी और मोहसिन खान की अगुवाई में लखनऊ सुपर जायंट्स के भारतीय गेंदबाजों के आक्रमण ने राजस्थान

रॉयल्स की मजबूत बल्लेबाजी को छह विकेट पर 159 रन पर रोक दिया। यह लगातार तीसरा मैच है जब राजस्थान रॉयल्स का शीर्ष क्रम पूरी तरह विफल रहा है, जिससे टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही है। अनुभवी गेंदबाज शमी (चार ओवर में 30 रन पर दो विकेट) एक बार फिर अपने कोशल के बूते सबसे अलग नजर आए, जबकि लंबे कद के मोहसिन (चार ओवर में 17 रन पर दो विकेट) बेहद अनुशासित रहे। उन्होंने शानदार स्विंग और उछाल भर गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान किया।

दोनों गेंदबाजों ने मिलकर राजस्थान के चार प्रमुख बल्लेबाजों को पेवेलियन भेजा। शमी ने यशस्वी जायसवाल (22) और ध्रुव जुरेल (शून्य) को लगातार गेंदों पर आउट किया, जबकि मोहसिन ने वैभव सूर्यवंशी (11 गेंदों पर आउट रन) और शिमरॉन हेटमायर (18 गेंदों पर 22) को अलग-अलग स्पेल में आउट किया।

वैभव-यशस्वी का नहीं चला बल्ला

सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने बड़ी संख्या में डॉट गेंदें डालकर रॉयल्स को कम स्कोर पर रोक दिया। शमी (15 डॉट गेंदें) और मोहित (11 डॉट गेंदें) ने मिलकर 26 डॉट गेंदें फेंकीं, वहीं प्रिंस यादव ने भी 13 डॉट गेंदों का शानदार योगदान दिया। शमी ने यशस्वी जायसवाल को तेज बाउंडर पर फंसाया। जायसवाल ने अचानक उछाल लेने वाली गेंद पर हुक शॉट खेलने की कोशिश की और विकेटकीपर ऋषभ पंत ने एक हाथ से शानदार कैच लपक लिया। अनुभवी रविंद्र विकेट) एक बार फिर अपने कोशल के बूते सबसे अलग नजर आए, जबकि लंबे कद के मोहसिन (चार ओवर में 17 रन पर दो विकेट) बेहद अनुशासित रहे। उन्होंने शानदार स्विंग और उछाल भर गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान किया।

रोहित शर्मा ने बेशकीमती सलाह दी मैच की स्थिति के बारे में अधिक सोचे बिना शुरुआती 15 से 20 गेंद खेलो : तिलक



नई दिल्ली, 22 अप्रैल। तिलक वर्मा ने बुधवार को बताया कि रोहित शर्मा ने उन्हें आईपीएल 2026 में शतक लगाकर फॉर्म में लौटने में मदद की जब उन्होंने सलाह दी कि मैच की स्थिति के बारे में अधिक सोचे बिना शुरुआती 15 से 20 गेंद खेलो। तिलक ने नाबाद 101 रन बनाए जिससे मुंबई इंडियंस (एमआई) ने अपने पिछले मैच में गुरजराट टाइटंस को 99 रन से हराकर लगातार चार मैच में हार का सिलसिला तोड़ दिया। तिलक ने 45 गेंद की अपनी पारी में आठ चौके और सात छक्के लगाए। उनकी शुरुआत हालांकि धीमी रही थी और एक समय बाएं हाथ का यह बल्लेबाज 22 गेंद पर 19 रन बनाकर खेल रहा था।

तुम जानते हो कि क्या कर सकते हो?

तिलक ने वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बीच होने वाले मैच की पूर्व संख्या पर संवादाओं से कहा, मैं खास तौर पर रोहित भाई से बात कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा 15-20 गेंद खेलो और तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। उन्होंने कहा, अगर तुम 15 गेंदें खेल लेते हो तो हर कोई जानता है कि उसके बाद तुम क्या करोगे। बस स्थिति या किसी और चीज के बारे में मत सोचो, 15 गेंद खेलो और हम देखेंगे कि नतीजा क्या होता है। तिलक ने कहा, इससे मुझे आत्मविश्वास मिला और मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं 15 गेंद खेलूंगा और उसके बाद बाकी चीजें देखूंगा। जब मैंने ये 15 गेंद खेल लीं तो अपने आप ही व्यावहारिक रूप से समझ आ गया कि मुझे बड़े शॉट लगाने हैं।



प्रीमियर लीग : ब्राइटन ने चेल्सी को 3-0 से हराया, रोसेनियर के नेतृत्व में खराब दौर जारी

ब्राइटन, 22 अप्रैल। इंग्लैंड की शीर्ष फुटबॉल लीग प्रीमियर लीग में मंगलवार को ब्राइटन एंड होव एल्बियन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चेल्सी को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राइटन 50 अंकों के साथ अंकतालिका में छठे स्थान पर पहुंच गया, जबकि चेल्सी सातवें स्थान पर खिसक गई। चेल्सी ने अपने पिछले नौ मैचों में केवल एक जीत दर्ज की है और टीम का प्रदर्शन लगातार निराशाजनक बना हुआ है। ब्राइटन ने मैच के तीसरे ही मिनट में बढ़त बना ली, जब फेर्दी कादियोग्लू ने कॉर्नर से मिले मौके को गोल में बदल दिया। पहले हाफ में चेल्सी एक भी

शॉट लक्ष्य पर नहीं लगा सकी। दूसरे हाफ में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन टीम वापसी नहीं कर पाई। 56वें मिनट में जैक हिन्थोलवुड ने जॉर्जिनियो रटर के पास पर गोल कर बढ़त दोगुनी कर दी। इसके बाद डेनी वेल्बेक ने अंत में तीसरा गोल कर चेल्सी की हार पक्की कर दी। कोच लियाम रोसेनियर ने टीम में बदलाव किए, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा। चेल्सी लगातार पांचवें मैच में हार गई और इस दौरान एक भी गोल नहीं कर सकी। ब्राइटन की इस जीत से उसकी स्थिति मजबूत कादियोग्लू ने कॉर्नर से मिले मौके को गोल में बदल दिया। पहले हाफ में चेल्सी एक भी

अटापट्टू के हरफनमौला प्रदर्शन से श्रीलंका की वापसी, बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया

राजशाही, 22 अप्रैल। श्रीलंका ने कप्तान चमारी अटापट्टू के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर बुधवार को दूसरे वनडे मुकाबले में बांग्लादेश को 4 विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली। बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत खराब रही और टीम निर्यातित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। मलक्रो मंदारा ने पावरप्ले में दो झटके देकर दबाव बनाया। निगार सुलताना (58) और शारमिन सुलताना ने 45 रन की साझेदारी कर पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाजों ने वापसी करते हुए टीम को 45.5 ओवर में 165 रन पर समेट दिया। श्रीलंका की ओर से अटापट्टू ने 3 विकेट लिए, जबकि इनोका रणवीरा, निमाशा मीपागे और मंदारा ने भी अहम योगदान दिया। जवाब में श्रीलंका ने संयमित बल्लेबाजी की। कप्तान अटापट्टू ने 40 रन बनाकर मजबूत शुरुआत दी, जिसके बाद हर्षिता समरविक्रमा (50) और हंसिमा करुणारत्ने (40) ने 77 रन की साझेदारी कर जीत की राह आसान कर दी। टीम ने 38.2 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

डोपिंग विवाद में फसे मोहम्मद नवाज, पीसीबी की साख पर उठे सवाल

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद आईसीसी ने जांच शुरू कर दी है। इस विवाद के चलते पीसीबी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और इंग्लैंड में उनका काउंटी अनुबंध भी रद्द हो गया है। पाकिस्तान टीम के अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज इन दिनों एक गंभीर विवाद में घिर गए हैं। हाल ही में उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हलचल मच गई है। यह मामला कथित तौर पर रिक्रिप्शनल ड्रग के इस्तेमाल से जुड़ा है और इसकी जांच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एंटी-डोपिंग नियमों के तहत की जा रही है।

52वीं राज्य स्तरीय शर्मा-माथुर क्रिकेट प्रतियोगिता मेहर की जीत में रॉविन व इजहार चमके

जयपुर, 22 अप्रैल। बनीपाक क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित 52वीं राज्य स्तरीय शर्मा-माथुर क्रिकेट प्रतियोगिता के अन्तर्गत आज खेले गये मैच में रॉविन सिंह 124 रन नाबाद की शतकीय पारी तथा इजहार खान 31 रन व 35 रन पर 3 विकेट के ऑलराउण्ड प्रदर्शन की बदौलत मेहर क्रिकेट क्लब ने यंग फ्रेण्ड्स क्रिकेट क्लब को 82 रन से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।

टापे जीतकर मेहर क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुये रॉविन सिंह 124 रन (114 गेंद, 7 चौके, 6 छक्के), उर्मित सिंह 52 रन (50 गेंद, 8 चौके, 2 छक्के) ने मिलकर 15 ओवर में 124 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत की। मध्यक्रम में मानव रोहा 34 रन, इजहार खान 31 रन, आशीष शर्मा 20 रन की मदद से निर्धारित 40 ओवर में

4 विकेट खोकर 302 रन बनाये। गेंदबाजी में यंग फ्रेण्ड्स क्रिकेट क्लब की ओर से सचिन, अर्पित, मयंक स्वामी तथा देवेश शर्मा प्रत्येक 1-1 विकेट लेकर संफल गेंदबाज रहे। जवाबी पारी में विशेष बेनीवाल 54 रन, अर्जित 43 रन, दीपक बड़ेतिया 27 रन तथा शेर सिंह यादव 22 रन को छोड़कर यंग फ्रेण्ड्स क्रिकेट क्लब का कोई भी बल्लेबाज इजहार 35 रन पर 3 विकेट, आशीष शर्मा 64 रन पर 2 विकेट, निविन सिंह 50 रन पर 2 विकेट की गेंदबाजी के समक्ष 34.1 ओवर में 220 रन बनाकर यंग फ्रेण्ड्स क्रिकेट क्लब की पूरी टीम सिमट गयी। इस मैच का मैन ऑफ द मैच रॉविन सिंह मेहर क्रिकेट क्लब रहे।

राजस्थान के विनीत व अंशु बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में देंगे कोचिंग

जयपुर, 22 अप्रैल। राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ी व क्रिकेट कोच विनीत सक्सेना व अंशु जैन को बीसीसीआई ने पॉल्डचेरी व सिक्किम में आयोजित होने वाले बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सिलेंस प्रशिक्षण शिविर में कोच की जिम्मेदारी दी है। विनीत सक्सेना को क्रिकेट एसोसिएशन पॉल्डचेरी के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस पॉल्डचेरी में 11 मई से 6 जून तक व अंशु जैन को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ सिक्किम के रांगपो स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में 11 मई से 9 जून तक आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर में कोचिंग देंगे।

कोपा इटालिया : इंटर मिलान ने दो गोल से पिछड़कर कोमो को 3-2 से हराया

मिलान, 22 अप्रैल। इटली की प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा इटालिया में इंटर मिलान ने शानदार वापसी करते हुए सेमीफाइनल के दूसरे चरण में कोमो को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पहला चरण गोलरहित रहने के बाद खेले गए इस मुकाबले में इंटर ने दो गोल से पिछड़ने के बावजूद जीत दर्ज कर खिताब की दौड़ में खुद को मजबूत बनाए रखा है। कोमो के लिए मार्टिन बादुरीना और कप्तान लुकास दा कुन्हा ने गोल कर टीम को बढ़ाव दिलाई। इसके बाद इंटर मिलान की ओर से हाकान चाल्हानोग्लू ने शानदार खेल दिखाते हुए दो गोल किए। उन्होंने पहले जोरदार लंबी दूरी का शॉट लगाकर टीम को वापसी कराई और फिर 86वें मिनट में हेडर के जरिए बराबरी दिलाई। मैच के 89वें मिनट में पेटार सुचिचने चाल्हानोग्लू के साथ बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए फिज्जली गोल दागा। इंटर मिलान अब फाइनल में पहुंच गया है, जो 13 मई को खेला जाएगा। दूसरी सेमीफाइनल में अटलंटाला और लाजियो के बीच मुकाबला होना है, जहां पहला चरण 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुआ था। इंटर मिलान इस समय इटली की शीर्ष लीग सीरी ए में भी शीर्ष पर चल रहा है और इस सप्ताहांत खिताब अपने नाम कर सकता है।

अगर अक्षर पटेल को खुद पर भरोसा नहीं तो.. : आरोन फिंच



नई दिल्ली, 22 अप्रैल। दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के पास आईपीएल 2026 में सबसे मजबूत स्पिन बॉलिंग जोड़ियों में से एक कप्तान अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की जोड़ी है। एक डिफेंस करने में एक्सपर्ट है जबकि दूसरा ऐसा रिस्ट स्पिनर है, जिसे बल्लेबाज हमेशा हाथ से पढ़ नहीं पाते। फिर भी सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ दोनों ने मिलकर सिर्फ चार ओवर डाले। दिल्ली को इस मैच में 47 रनों से हार मिली। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की (68 गेंदों में नाबाद 135) शतकीय पारी की बदौलत एसआरएच ने 242/2 का स्कोर खड़ा किया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान आरोन फिंच मैच में अक्षर द्वारा सिर्फ दो ओवर डालने से हैरान है।

अगर खुद पर भरोसा नहीं तो...

आरोन फिंच ने ईएसपीएन क्रिकइंफो के टाइम आउट शो में कहा, "हम सब सिर खुजा रहे हैं, है ना आपके दो भारतीय प्रीमियर स्पिनर कप्तान अक्षर पटेल (2-0-23-1) और कुलदीप यादव (2-0-30-0) दोनों ने मिलकर सिर्फ चार ओवर डाले, जबकि पटेल टाइम ऑफ स्पिनर नितीश राणा ने चार ओवर डाले। मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं बनता।" राणा डीसी के सिधले दो मैचों में नहीं खेले थे, वह एसआरएच के खिलाफ पावरप्ले में गेंदबाजी करने आए। आईपीएल में उनके 122 मैचों में यह 27वीं बार था, जब उन्होंने गेंदबाजी की और सिर्फ दूसरी बार उन्होंने अपना पूरा कोटा डाला। डीसी ऐसा गेंदबाज को चाहती थी, जो गति कम करे और अभिषेक शर्मा व डेविस हेड से गेंद दूर टर्न कराए।

सैफ महिला चैम्पियनशिप में मेजबान भारत ग्रुप-बी में बांग्लादेश और मालदीव के साथ

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। सैफ महिला चैम्पियनशिप के आधिकारिक ड्रा में मेजबान भारत को ग्रुप बी में बांग्लादेश और मालदीव के साथ रखा गया है। ड्रा का आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित सैफ सचिवालय में किया गया। यह टूर्नामेंट 25 मई से 6 जून तक गोवा के मडगांव में आयोजित होगा और सभी मुकाबले पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले जाएंगे। ग्रुप ए में नेपाल, श्रीलंका और भूटान को रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में भारत, बांग्लादेश और मालदीव शामिल हैं। दोनों ग्रुप से शीर्ष दो टीमों सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। टूर्नामेंट की सीडिंग 21 अप्रैल को जारी फीफा महिला विश्व रैंकिंग के आधार पर की गई।

कुक का अजीबोगरीब बयान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जैकब बेथल को आईपीएल 2026 छोड़ने की दी सलाह

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर एलिस्टर कुक ने युवा बल्लेबाज जैकब बेथल को आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का बीच में ही साथ छोड़कर इंग्लैंड लौट आना चाहिए और काउंटी क्रिकेट में वार्लिकशायर के साथ खेलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बेंच पर बेंचकर वह अपना बहुमूल्य समय गंवा रहे हैं। बेथल ने हाल ही में टी20 विश्व कप में दमदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ 45 गेंदों में शतक जड़ा था। उन्होंने टूर्नामेंट के सबसे तेज शतर में से एक लगाया था और अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाया था। हालांकि आईपीएल 2026 में जैकब बेथल को मौका मिलने का इंतजार है। वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का हिस्सा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के पास विदेशी विकल्प के रूप में फिल साॅल्ट, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड और जोश हेजलवुड मौजूद हैं और इस वजह से जैकब बेथल टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं। कुक का मानना है कि इस समय जैकब बेथल की स्थिति उसके करियर के इस चरण के लिए बिल्कुल आदर्श नहीं है। स्टिक टू क्रिकेट पॉइकाउंट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि टॉप ऑर्डर में बेथल की क्षमता पहले से ही स्पष्ट है और उन्हें लगातार खेलने के मौके देकर समर्थन देने की जरूरत है। कुक ने कहा, टॉप ऑर्डर बैटिंग के लिए, सिडनी में जिस तरह उसने उन अटैक के खिलाफ उन कंडीशंस में खेला... मैंने वहां एक खिलाड़ी को देखा है और मुझे यकीन है कि यह खिलाड़ी ऑपनिंग कर सकता है। अगर वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकता है, तो वह ऑपनिंग भी कर सकता है।" उन्होंने आगे कहा, बेथल को वाकई ऑपनिंग नहीं करनी चाहिए।



राजस्थान रॉयल्स के मैस्कोट म्यू सिंह ने युवा फैस से बातचीत की

जयपुर, 22 अप्रैल। वर्ल्ड ट्रेड पार्क और गौरव टावर में आज शाम "हल्ला बोल" का जोश देखने को मिला, जब राजस्थान रॉयल्स के मैस्कोट, म्यू सिंह, युवा फैस और परिवारों से बातचीत करने के लिए शानदार तरीके से आए। शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच, अपनी खास मूंछों और पर्णों के लिए जाने जाने वाले म्यू सिंह ने सैकड़ों बच्चों के साथ कई मजेदार एंक्टिविटीज में हिस्सा लिया।

युग पुरुषों की शौर्य गाथाएँ आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा हैं- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने चूरु में "शौर्य के साथ संकल्प दिवस" पर ले.जनरल सगत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया

चूरु/जयपुर, 22 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान वीरों एवं रणबाँकुरों की धरती है। यहां के सपनों ने अनेक युद्धों में वीरता एवं शौर्य का परिचय दिया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ को नमन करते हुए कहा कि वीर भूमि के इस सपूत ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर साहस का अप्रतिम उदाहरण पेश किया। उन्होंने कहा कि इन युगपुरुषों से युवाओं को दिशा मिलती है तथा इनकी शौर्य गाथाएँ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम करेंगी।

शर्मा बुधवार को चूरु में आयोजित लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की मूर्ति अनावरण एवं 'शौर्य के साथ संकल्प दिवस' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने 19 साल की उम्र में बीकानेर रियासत की सेना में सैन्य जीवन से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पद्म भूषण और परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के सम्मान में चूरु स्टेडियम का नाम सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सैनिक कल्याण के लिए सजग होकर निरन्तर कार्य कर रही है। डीडवना-कुचामन में राजस्थान के पहले एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर की स्थापना की तथा नवीन जिला सैनिक कल्याण



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को चूरु में आयोजित लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ मौजूद थे।

कार्यालय खोले जा रहे हैं। साथ ही, आरटीडीसी के सभी होटलों और गेस्ट हाउसों में वीरगाथाओं को 50 प्रतिशत और सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल की प्रतिमा

अनावरण से नौजवानों को नई दिशा मिलेगी एवं आगामी पीढ़ी इससे प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर ने लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के बलिदान एवं साहस का जिक्र करते

हुए कहा कि भारत-चीन युद्ध में नाथूला बॉर्डर पर उन्होंने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने आजाद भारत की सेना में विभिन्न पदों पर अपना कौशल सिद्ध किया। चूरु में जन्मे सिंह का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर व पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने ले.जनरल सगत सिंह के 1971 के युद्ध में योगदान को याद किया।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह भारत की सैन्य गौरवगाथा के अमर प्रतीक हैं। 1971 के युद्ध में मेघना नदी पार कर उनकी कुशल रणनीति ने पाकिस्तान को पराजित किया और बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार नायक, पैरालिंपिक कमिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेन्द्र झाड़िया, विधायक हरलाल सहायण सहित, विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

क्या ममता बनर्जी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अदालत ने राज्य के वकीलों द्वारा प्रस्तुत कानूनी तर्कों को भी खारिज कर दिया। ईडी अधिकारियों के मौलिक अधिकारों को लेकर दिए गए तर्कों को संक्षेप में खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि कार्यपालिका के हस्तक्षेप की वास्तविकता निर्विवाद है।

मतदान दिवस नजदीक आते ही ममता बनर्जी का मानसिक संतुलन बिगड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है और वे एक के बाद एक गलतियाँ कर रही हैं। उनके चुनावी भाषणों में न तो राजनीतिक सामग्री है और न ही नीतिगत चर्चा। वे असंबन्धित मुद्दों पर टिप्पणी कर रही हैं।

एक चुनावी सभा में उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार का उल्लेख करते हुए कहा कि इस घटना के जवाब में महात्मा गांधी ने एक कविता लिखी थी, जिसे उन्होंने रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद लिखी गई कविता बताया।

उनकी इस तरह की गलतियाँ लगातार सामने आ रही हैं और लोग अब

■ ममता जी के वकीलों की मजबूत टीम ने यह दलील दी कि ईडी को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इन वकीलों की दलील को दो सैकड़ में अस्वीकार करते हुए कहा। सरकार द्वारा छापे की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का मामला साफ दिख रहा है कहकर ममता जी के खिलाफ सख्त "ऑब्जर्वेशन" किए।

शायद इन पर ध्यान देना भी बंद कर चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यदि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। यदि बड़ी संख्या में तैनात केन्द्रीय बल हिंसा को रोकने में सफल रहते हैं और लोगों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने दिया जाता है, तो तुणमूल कांग्रेस के लिए स्थिति कठिन हो सकती है।

लंबे समय से सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, सत्तारूढ़ तंत्र के लोगों द्वारा कथित आपराधिक दबाव और एक सरकारी अस्पताल में एक युवा महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या जैसी घटनाओं ने सरकार के प्रति नकारात्मक माहौल

बनाया है। इसके अलावा, ममता बनर्जी को मुस्लिम मतदाताओं पर पकड़ भी कमजोर पड़ती दिखाने दे रही है। समुदाय के भीतर से कई आवाजें उनके और उनकी सरकार के खिलाफ उठ रही हैं। इन बदलावों को देखते हुए वे बहुसंख्यक समुदाय की सहानुभूति हासिल करने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करती नजर आ रही हैं।

इस चुनाव के नतीजे काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेंगे कि मुस्लिम वोट कितनी हद तक विभाजित होते हैं। जितना अधिक वोट तुणमूल कांग्रेस से दूर जाएगा, उतना ही अधिक लाभ भाजपा को होगा।

ट्रंप ने ईरान के साथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उसकी कूटनीतिक स्थिति को पुनः स्थापित करने और निवेश आकर्षित करने की कोशिश है। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता पूँजी के संकट से जुड़े रहे इस्लामाबाद के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए चुनौती है, बल्कि सऊदी अरब के साथ उसके सुरक्षा समझौते और खाड़ी से ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भरता के कारण उसे संघर्ष में खींच सकती है।

पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (पीआईडी) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, तेल की बढ़ती कीमतें आयात बिल बढ़ाती हैं, महंगाई का दबाव बढ़ाती हैं और विनियम दर पर दबाव डालती हैं, जिससे आर्थिक गतिविधि धीमी पड़ती है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया, "स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो अभी बंद है, अगर यह बंद लंबे समय तक जारी रहता है, तो औद्योगिक लागत बढ़ा सकता है और समग्र व्यापारिक विश्वास को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा, ऊंची ऊर्जा कीमतें व्यापार घाटा बढ़ा सकती हैं और बाहरी वित्तीय जरूरतों पर दबाव डाल सकती हैं।"

अक्सर धार्मिक उग्रवाद के

आंतरिक खतरों और कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समयाग्रस्त देश के रूप में देखे जाने वाले इस्लामाबाद ने इस संघर्ष में अपनी तटस्थता और दोनों देशों से अच्छे संबंधों का लाभ उठाते हुए "मध्यस्थ" की भूमिका निभाने के मौके को हाथों हाथ लिया। पिछले सप्ताह तेहरान की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इजरायल और लेबनान के बीच युद्धविराम कराने के साथ-साथ

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने में भी प्रगति की थी, हालांकि यह अल्पकालिक साबित हुआ। कई जगहों पर पाकिस्तान की छवि एक कमजोर अर्थव्यवस्था और आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश की रही है। हालांकि, वह मुस्लिम दुनिया का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश है, जिसके पास 6 लाख सैनिकों की सेना है, इस नाते इस्लामाबाद मानता है कि वह अब तक अपनी क्षमता से कम प्रभाव डाल रहा था।

जैसे-जैसे एक नयी बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था आकार ले रही है, पाकिस्तान के नेता अपनी सैन्य ताकत का उपयोग करते हुए अधिक प्रभाव

हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कमजोर अर्थव्यवस्था और अस्थिर राजनीति की कमियों को संतुलित किया जा सके। हाल के समय में पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरी स्पष्ट रही है, जहाँ पैसे बचाने के लिए योजना बिजली कटौती की जा रही है और सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर का आपातकालीन ऋण लिया गया है। वह उम्मीद कर रहा है कि बढ़ती वैश्विक साख से उसे अधिक निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। हालांकि, इसके लिए करों में कमी और मजबूत कानून जैसे आर्थिक सुधार भी जरूरी होंगे। पाकिस्तान पहले ही अमेरिका के साथ कई आर्थिक समझौते कर चुका है। यदि वे वातांश युद्ध को समाप्त करने में सफल रहती हैं, तो इससे इस्लामाबाद की विश्वसनीयता और बढ़ेगी और नए अवसर खुलेंगे।

लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि यदि बातचीत विफल होती है, तो पाकिस्तान पर भी इसका दोष आ सकता है। पहले से ही इस्लामाबाद पर अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका का विरोध करते हैं।

आईआरएस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

घर का पुराना नौकर है। उसे करीब एक महीने पहले पैसे में गड़बड़ी के आरोप में काम से निकाला गया था। राहुल मीणा राजस्थान के अलवर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, वह करीब आठ महीने तक आईआरएस अफसर के घर पर नौकर था। वह आईआरएस अफसर के घर के हर कोने से वाकिफ था। उसे यह भी पता था कि युवती के माता-पिता कब वॉक या जिम के लिए घर से निकलते हैं।

प.बंगाल की 84 एससी/एसटी बहुल सीटें ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एससी और 7 एसटी सीटें जीतीं, जबकि टीएमसी का प्रदर्शन भी लगभग बराबरी पर रहा, क्योंकि पार्टी ने 3.6 एससी सीटें हासिल कीं।

इस चुनाव में टीएमसी और भाजपा दोनों ही अपने पक्ष में वोटों के रुझान (स्विंग फैक्टर) पर भरोसा कर रही हैं। इन पार्टियों के प्रमुख नेता, जिनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री

ममता बनर्जी शामिल हैं, ने जंगलमहल क्षेत्र के पुरलिया, बंकुरा, पश्चिम मिदनापुर और झारग्राम जैसे इलाकों में व्यापक प्रचार किया है।

इस चुनाव में एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र उत्तर बंगाल के रूप में उभरा है, जहाँ एससी और एसटी आवादी का मिश्रण है और जिसमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी तथा पूर्व और पश्चिम दिनाजपुर जिले शामिल

हैं। बांग्लादेश से सटे दक्षिण बंगाल की एससी-बहुल मातुआ बेल्ट भाजपा के लिए एक खास लक्ष्य रही है, जहाँ वह राजवंशी समुदाय के बीच भी अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं टीएमसी को उम्मीद है कि वह अपने स्थानीय विकास कार्यों और "लक्ष्मी भंडार" जैसी कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर इन 84 सीटों पर अपना प्रभाव बनाए रखेगी।

संजय झा फिर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निशांत कुमार को लगातार पार्टी गतिविधियों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। वे पार्टी कार्यालय में बैठकों के साथ-साथ कार्यक्रमों से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि वे अगले महीने बिहार यात्रा पर भी निकल सकते हैं, जिससे जदयू के जनसंपर्क अभियान को और गति मिलने की उम्मीद है।

MARUTI SUZUKI

NEXA

EXPERIENCE GRAND IN EVERY DRIVE WITH THE GRAND VITARA.

NOW AT ₹ 9 999
₹ 8 999 PER MONTH



EFFECTIVE PRICE OF
₹ 9.92 LAKH*

GRAND VITARA



R17 MACHINED ALLOY WHEELS



AUTO PURIFY WITH PM2.5 DISPLAY



8-WAY DRIVER POWERED SEAT



EV MODE



6 AIRBAGS AS STANDARD



SCAN TO CONNECT TO A SHOWROOM NEAR YOU

T&C available at your nearest dealership. Creative visualization. Images used are for illustration purposes only. For details on safety features (including airbags), refer owner's manual. NEXA dealers exclusively provide all offers, which vary by model and variant. Offers are subject to availability of stock. *Ex. showroom Price of ₹ 10.77 lakh, Consumer Offer (-) ₹ 25,000, Exchange Bonus (-) ₹ 30,000, Corporate Offer (-) ₹ 10,000 = ₹ 9.92 lakh. The actual effective price mentioned may vary based on the customer's eligibility, profile, and applicable offers at the time of purchase. Offer valid on Grand Vitara Sigma Variant. Maruti Suzuki may withdraw offers without notice. Offer valid till limited period. Features and accessories shown may not be part of the standard fitment. *EMI @ Rs 8 999* is a scheme illustration for upgrade from Brezza to Grand Vitara Sigma variant. Balloon Finance EMI is calculated @ 9.5% rate of interest; Balloon EMI is 30% of the total loan amount and loan tenure of 5 years. Balloon Finance Scheme provided by select financiers.

राष्ट्रदूत हिन्दू संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वैस्ट्री मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513 कोटा कार्यालय: पलायवा हाऊस, छत्रपति सिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033 बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालोर कार्यालय: - जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल परिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय: - जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरु कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरु, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908